● वर्ष-2
● अंक-290
रायपुर, गुरुवार
27 जुलाई 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पेश किया, लोकसभाध्यक्ष ने स्वीकार किया

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 जुलाई को नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पेश किया था। मोर्चे के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि भारत के 26 विपक्षी दलों के गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा पर संसद में बोलने के लिए प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। विपक्ष मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है जो 3 मई से जातीय हिंसा से प्रभावित है, जिसमें दो महिलाओं को नग्न घुमाने की घटना भी शामिल है। जिसके वीडियो की हर तरफ काफी आलोचना हो रही है। हालांकि, अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है।

कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई कहते हैं, भाजपा इसे हार जीत का मुद्दा बना रही है। %इंडिया% के लिए तो यह लोकतंत्र की लड़ाई है। एक तरफ तो केंद्रीय गृह अमित शाह कहते हैं कि वे मणिपुर पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में वे मल्लिकार्जुन खरगे और अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखते हैं।

सवाल राष्ट्र की सुरक्षा का

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव नहीं बल्कि ढ्ढ.ग्र.ष्ठ.ढ्ढ. के घटक दलों द्वारा सामूहिक तौर पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 83-84 दिनों से मणिपुर में जो स्थिति बनी हुई है उस पर क़ानून-व्यवस्था चरमरा गई है, समुदाय के बीच विभाजन हो गया है। तिवारी ने दावा किया कि वहां सरकार नाम की चीज़ नहीं रह गई है। इन तथ्यों ने हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि ढ्ढ.ग्र.ष्ठ.ढ्ढ. के घटक दलों की सामूहिक मांग है कि सभी काम को एक तरफ रखते हुए कल ही इस प्रस्ताव के ऊपर, प्राथमिकता रखते हुए पर इस चर्चा होनी चाहिए। संख्याबल के सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा कि सवाल संख्या का नहीं बल्कि नैतिकता का है। बुनियादी सवाल यह है कि जवाबदारी किस की है। सदन में जब इस पर मतदान होगा तब नैतिकता की

कसौटी पर कौन कहां खड़ा है। सवाल राष्ट्र की सुरक्षा का है।

प्रस्ताव को सदन के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। जबकि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है, प्रभावी सीटें 537 हैं और खाली सीटें केवल 6 हैं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी मोदी सरकार बेफिक्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का भविष्य पहले से तय है। संख्याबल के आधार पर भाजपा मजबूत है। लोकसभा में विपक्ष के 150 से भी कम सांसद हैं। 272 बहुमत का आंकड़ा होता है। भाजपा अपने दम पर 303 है। जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन के पास 331 सदस्य हैं।

अविश्वास प्रस्ताव के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मणिपुर के मामले में विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार, विपक्षी दलों की मांग स्वीकार नहीं कर रही थी। संसद में पीएम से बयान देने की मांग की गई तो वह भी नहीं मानी। प्रधानमंत्री, विपक्ष की मांग को हल्के में लेते रहें।

2018 में मोदी सरकार के विरूद्ध अविश्वास लाया था विपक्ष

पूर्व एनडीए सहयोगी टीडीपी द्वारा 2018 में मोदी प्रशासन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर किया गया था, जब पार्टी ने दावा किया था कि केंद्र आंध्र प्रदेश को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने में विफल रहा है। यह प्रस्ताव टीडीपी और बीजेपी की साझेदारी टूटने के बाद पेश किया गया था। प्रस्ताव को कई विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था, हालांकि, शिवसेना कार्यवाही से दूर रही और नवीन पटनायक की बीजेडी ने सदन से वॉक आउट किया था। हालाँकि, विपक्ष ने चर्चा को कृषि संकट, आर्थिक विस्तार और मॉब लिंचिंग में वृद्धि सहित मामलों पर प्रशासन की आलोचना करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने विवादास्पद 12-बहस के बाद लोकसभा में प्रस्ताव को हरा दिया। 126 सांसदों ने इस उपाय के पक्ष में मतदान किया, लेकिन 325 सांसद इसके खिलाफ थे।

पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच नोकझोंक

तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच नोकझोंक, जिसमें प्रधानमंत्री का 90 मिनट से अधिक का संबोधन भी शामिल था, जो 12 घंटे की बहस का मुख्य आकर्षण रहा। चर्चा के दौरान अपने संबोधन के समापन पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और उन्हें गले लगाया। लेकिन वहां से वापस लौटते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मारने वाला वीडियो भी चर्चा का विषय रहा था। बाद में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने सभी दलों से इस कदम की अनदेखी करने का आह्वान किया और कांग्रेस पर मोदी हटाओ की मानसिकता के साथ काम करने का आरोप लगाया, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास मत को विपक्ष के अहंकार का परिणाम बताया।

इन दिनों

✍ जितेंद्र

अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा का ईरानी दांव

मणिपुर हिंसा को लेकर लोकसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को मंजूरी मिल गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों खेमे इसे अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं। यूं भी कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया, दोनों को इसमें अपना सियासी फायदा नजर आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा को %मोदी% के %ईरानी दांव% पर भरोसा है, तो वहीं %विपक्ष% इस हार के सौदे में अपनी जीत मानकर चल रहा है। मणिपुर हिंसा पर, विपक्षी दल लंबे समय से प्रधानमंत्री द्वारा बयान देने की मांग कर रहे थे। सत्ता पक्ष ने प्रधानमंत्री की जगह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान दिलाने की बात कही, जिसके लिए विपक्ष तैयार नहीं हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई कहते हैं, देखिये, ये हार जीत का सवाल नहीं है। यह विपक्ष का संवैधानिक दायित्व है। ये इंसाफ की लड़ाई है। विपक्षी दलों का गठबंधन %इंडिया% चाहता है लोकतंत्र जीवित रहे। दरअसल, मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की स्क्रिप्ट कई दिनों से लिखी जा रही थी। सत्ताधारी पार्टी यह बात जानती थी कि विपक्ष, सदन में प्रधानमंत्री से बयान दिलवाने की जिद से पीछे नहीं हटेगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में मणिपुर को लेकर बहुत कुछ क्लीयर कर दिया था। उसमें भाजपा सांसदों को यह संदेश दिया गया था कि वे मणिपुर हिंसा पर विपक्ष को करारा जवाब दें। उसी बैठक में पीएम की तरफ से ऐसा इशारा भी हुआ था कि जल्द ही विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। भाजपा सांसदों से कहा गया कि अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को मणिपुर का सच बताएं। बैठक में मौजूद हरियाणा के एक सांसद का कहना था। अविश्वास प्रस्ताव से भाजपा को डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहलवानी में कई तरह के दांव होते हैं। उसमें से एक %ईरानी दांव% भी होता है, जिसमें बड़े कद काठी वाले पहलवान को फायदा मिलता है। वजह, बड़े कद वाला पहलवान, हल्के पहलवान को आसानी से उठा सकता है। अगर सामने वाले पहलवान का वजन भी कुछ कम है, तो उसे उठाकर पीठ के बल पटका जा सकता है। इससे बड़े कद वाला पहलवान जीत जाता है। पीएम मोदी के साथ भी कुछ वैसा ही है। अविश्वास प्रस्ताव पर हार से विपक्ष के दो मकसद पूरे होंगे। एक तो इंडिया की एकता का टेस्ट होगा और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा पर बोलने के लिए बाध्य करने के बाद लोगों को बताया जाएगा कि ये विपक्षी दलों की जीत है। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में पीएम मोदी भाग लेते हैं तो इसे विपक्षी खेमा अपने लिए एक मजबूत कदम के तौर पर देख रहा है। दूसरा, विपक्षी दलों को यह शिकायत रही है कि उन्हें सदन में बोलने का पर्याप्त समय नहीं मिलता।

भारत के चावल निर्यात बैन से अमेरिका में मची खलबली

वाशिंगटन। भारत के गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद पूरे अमेरिका में चावलों की कमी दर्ज की गई है। लोग चावल को पहले से ही खरीदकर रखने की होड़ में लग गए हैं। ऐसे में बढ़ती मांग के जवाब में, कई दुकानों ने ग्राहकों द्वारा खरीदे जाने वाले चावल के बैग की संख्या पर प्रतिबंध लगा दिया है

अमेरिका में रहने वाली अरुणा ने बताया कि उन्होंने सोना मसोरी चावल के लिए अमेरिका में स्थानीय पटेल ब्रदर्स, अपना बाजार, लोटे प्लाजा और अन्य दक्षिण एशियाई किराने की दुकानों को छान मारा। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें चावल का सिर्फ एक बैग ही मिला। उन्होंने कहा कि वह 10 से अधिक दुकानों पर चावल

खरीदने के लिए गईं, लेकिन निराशा हाथ लगी। उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे सोना मसोरी की तलाश शुरू की और शाम 4 बजे तक चावल का एक बैग सामान्य कीमत से तीन गुना ज्यादा कीमत पर मिला। पूरे अमेरिका में अरुणा जैसे कुछ लोग चावल की बोरियां घर लाने में कामयाब रहे, जबकि कई अन्य ने खरीद पर प्रतिबंध की सूचना दी

भारत ने आगामी त्योहारों के दौरान घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और खुदरा कीमतों को काबू में रखने के लिए गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर 20 जुलाई को प्रतिबंध लगा दिया था। शीर्ष निर्यातक भारत द्वारा रोक लगाने के बाद कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे वैश्विक खाद्य बाजारों पर तनाव बढ़ गया है जो पहले से ही खराब मौसम और बदतर स्थिति से परेशान हैं।

शिशु फार्मूला की कमी आई याद

गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध ने कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका में शिशु फार्मूला की कमी को याद दिला दिया है। अमेरिका में जिन शहरों में चावल की सबसे ज्यादा कमी पता चली है, वहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। इसके अलावा, प्रतिबंध का असर अमेरिका के बड़े-बॉक्स गोदामों पर भी महसूस किया जा रहा है। मैरीलैंड में सपना फूड्स, जो आमतौर पर डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया या डीएमवी क्षेत्र में सौ से अधिक खुदरा स्टोर और रेस्तरां को चावल भेजता था। वहीं, अब न्यू जर्सी और अन्य जैसे पड़ोसी राज्यों से भी थोक मांग आ रही है।

सोना मसोरी की सबसे ज्यादा मांग

बाल्टीमोर के पास थोक विक्रेता तरूण सरदाना ने मंगलवार को बताया कि पिछले सप्ताह गुरुवार को प्रतिबंध की खबर आते ही चावल की मांग में तेजी आ गई थी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सोना मसोरी चावल के लिए बहुत सारे फोन आ रहे हैं।

दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के पुनर्विकसित परिसर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह इस साल सितंबर में होने वाली भारत के जी20 नेताओं की बैठक की मेजबानी करेगा।

प्रमुख समाचार

कांग्रेस सत्ता के लिए घोषणा करने में नंबर 1 : सिंधिया

भोपाल। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने है। चुनावी राज्य होने के नाते मध्य प्रदेश में राजनीति भी लगातार बढ़ती जा रही है। भाजपा फिलहाल सत्ता में है। 2020 में सियासी उठापटक के बाद भाजपा सत्ता में आई थी। कांग्रेस एक बार फिर

से चुनाव जीतना चाहती है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि सत्ता की कुर्सी के लिए देश की पुरानी पार्टी घोषणाएं करने में नंबर वन है। आपको बता दें कि कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे थे। हालांकि, 2020 में वह भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए घोषणाएं करने में नंबर 1 पर आती है लेकिन फिर जनता को पूरी तरह से भूल जाती है। उन्होंने कहा कि जनता उनके इस व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ है। भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है...हमारी एक सोच और विचारधारा है, वह है जन सेवा, जन कल्याण और गरीब कल्याण। इसी के आधार पर हमारी सरकार चलती है।

प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की फायरिंग, एक की मौत

पटना। बिहार के कटिहार जिले में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बिहार पुलिस के मुताबिक, उत्तेजित भीड़ ने बिजली विभाग के दफ्तर पर पथराव और तोड़फोड़ की। बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कथित तौर पर गोलीबारी की जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं। हालांकि, इसको लेकर भाजपा नीतीश सरकार पर हमलावर है गई है। बिहार के कटिहार में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प पर भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरियां मांगने वालों पर लाठीचार्ज कराया। अब, उनके राज में, बिजली मांगने पर लोगों को गोली मारी जा रही है...न सुशासन, न जनता को सुविधाएं। यह अत्याचार की सरकार है...कोई उम्मीद नहीं बची है...। वहीं, भाजपा ने ट्वीट कर कहा कि आज फिर बिहार की मिट्टी खून के कतरे से सन गई। तानाशाह महागठबंधन सरकार हर रोज बिहारियों को जख्म पर जख्म दे रही है।

वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव से 55.60 लाख का नुकसान

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद को बताया कि 2019 से वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव से हुए नुकसान के कारण रेलवे को 55 लाख रुपये से अधिक का नुकसान

हुआ है। वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि ऐसी घटनाओं के जवाब में, पथराव में शामिल 151 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किसी यात्री की जान जाने या किसी यात्री के सामान की चोरी या क्षति की कोई घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने विस्तार से बताया कि वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 (जून तक) के दौरान, पथराव की घटनाओं में वंदे भारत ट्रेनों को हुए नुकसान के कारण भारतीय रेलवे को 55.60 लाख रुपये का नुकसान हुआ। रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों के जीवन की सुरक्षा और बर्बरता के खिलाफ रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, आरपीएफ, जीआरपी/जिला पुलिस और नागरिक प्रशासन के समन्वय से, लोगों को पथराव और उसके परिणामों के खिलाफ जागरूक करने के लिए रेलवे पटरियों से सटे इलाकों में ऑपरेशन साथी चला रहा है।

प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन

नई दिल्ली। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के पुनर्विकसित परिसर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह इस साल सितंबर में होने वाली

भारत के जी20 नेताओं की बैठक की मेजबानी करेगा। सरकार ने जनवरी 2017 में राष्ट्रीय राजधानी में विश्व स्तरीय ढ्ढश्वष्ट की स्थापना करके प्रगति मैदान के पुनर्विकास के लिए ढ्ढञ्जक्क के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रिपोर्टों के अनुसार, परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 2700 करोड़ रुपये के आसपास है। इसे भारत मंडपम का नाम दिया गया है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने स्मारक टिकट और सिक्के जारी किए। पीएम मोदी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में पुनर्विकसित आईटीपीओ परिसर में पूजा की। उन्होंने कॉम्प्लेक्स के निर्माण में शामिल श्रमिकों से भी बातचीत की और उन्हें सम्मानित किया। पीएमओ ने सोमवार को कहा था कि प्रगति मैदान में पुरानी और पुरानी संरचनाओं की मरम्मत के बाद बनाई गई सुविधा को लगभग 2,700 करोड़ रुपये की लागत से एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया

दुश्मन के विमानों- मिसाइलों सतह से हवा में मार करने में सक्षम

नई दिल्ली। भारत स्वदेशी रूप से तीन-स्तरीय लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगी। ये

लगभग 400 किमी की दूरी पर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगी। रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया कि तीन-स्तरीय लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में उन्नत चरण में है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की परियोजना से भारत को ऐसी सीमाओं से हवा में दुश्मन की संपत्ति को मार गिराने की स्वदेशी क्षमताओं वाली सेनाओं के एक विशिष्ट समूह का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। मिसाइल प्रणाली में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तीन परतें होंगी, जो इसे विभिन्न दूरी पर लक्ष्य को भेदने की अनुमति देंगी। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का विकास कार्य तब हो रहा है जब भारत ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली एमआरएसएएम विकसित करने के लिए इजराइल के साथ काम किया है।

केन्द्रीय स्तर पर डीए 8 फीसदी तो अन्य भत्तों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी संभव

जितेंद्र भारद्वाज

केंद्र सरकार में कर्मियों को लेकर कई बड़े निर्णय लंबित हैं। ऐसा संभव है कि 180 दिन बाद सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए/डीआर में 8 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाए। वेतन में चार फीसदी डीए की वृद्धि, यह पहली जुलाई से देय है। डीए/डीआर की फाइल को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद यानी जनवरी 2024 में दोबारा से डीए में चार फीसदी की वृद्धि संभव है। उस वक्त डीए वृद्धि का ग्राफ पचास फीसदी के पार चला जाएगा। सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ऐसा होता है, तो बाकी के भत्ते भी स्वत ही 25 फीसदी बढ़ जाएंगे। रही बात पुरानी पेंशन की, तो केंद्रीय कर्मचारी संगठन किसी भी सूरत में इस मुद्दे से हटने को तैयार नहीं हैं। जेएफआरओपीएस के सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि केंद्र सरकार, कर्मियों के हितों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर दस अगस्त को जब संसद भवन के सामने दो लाख कर्मचारी एकत्रित होंगे, तो सरकार की नींद टूटेगी।

पे रिवाइज दस साल में जरूरी नहीं

केंद्र सरकार में कर्मियों को 42 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है। मौजूदा समय में महंगाई की दर को देखते हुए इसमें चार प्रतिशत की वृद्धि संभव है। इसके बाद जनवरी 2024 में भी चार फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है। सी. श्रीकुमार बताते हैं कि संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को बताया कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार इस संदर्भ में विचार नहीं कर रही। श्रीकुमार के मुताबिक, ये सरकार की मनमर्जी ही तो है। सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में पे रिवाइज हर दस साल में ही हो, यह जरूरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि पे कमीशन ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। कुछ माह बाद डीए 50 प्रतिशत के पार होने जा रहा है। ऐसे में नए डीए और एचआरए की संभावना बनना तय है। केंद्र सरकार ने ओपीएस की मांग पर एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी गठित कर दी। कर्मियों ने यह मांग तो कभी नहीं की। सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद %एनपीएस% एक आपदा है। एनपीएस में कर्मचारी को महज चार-पांच हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। हर सूरत में ओपीएस लागू कराएंगे।

वेतन आयोग गठन से मना किया

पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था। उसके तीन साल बाद आयोग की सिफारिशें लागू हुई। उस हिसाब से 2026 में वेतन रिवाइज होना चाहिए। इसके लिए 2023 में आयोग का गठन हो। अब केंद्र सरकार, ऐसे किसी आयोग के गठन से मना कर रही है। संसद में इस मुद्दे पर जो सवाल जवाब हुए, उनमें कहा गया है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच में कर्मियों के वेतन और पेंशन में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय 111 प्रतिशत बढ़ी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, मुद्रास्फीति के कारण वेतन और पेंशन के असली मूल्य में जो कटौती होती है, उसे पूरा करने के लिए डीए/डीआर दिया जाता है। अब डीए 42 प्रतिशत हो गया है। प्रति व्यक्ति आय तीन गुना हो गई। इसके साथ वस्तुओं के दाम भी उसी अनुरुप में बढ़े हैं। मतलब, केंद्र सरकार के कर्मी कम वेतन पर काम कर रहे हैं। पिछले तीन वेतन आयोगों की तरफ से कहा गया है कि जब डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाए, तो मुद्रा स्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में पे रिवाइज किया जाए। जनवरी 2024 में डीए 50 फीसदी के पार हो जाएगा। अब सरकार कह रही है कि वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सातवें वेतन आयोग में लिखा है कि जब डीए 50 प्रतिशत पर पहुंच जाए तो बाकी के भत्ते खुद ही 25 प्रतिशत बढ़ जाएंगे।

गृह मंत्री ने फाइलेरिया मुक्ति राष्ट्रीय अभियान एवं सहयोगी रेडियों 91.2 एफएम का किया शुभारंभ

दुर्ग। प्रदेश के लोक निर्माण कृषि व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू आज स्वामी विवेकानंद सभागार पदमनाभपुर में आयोजित ग्रामीण स्तरीय मितानिन सम्मेलन एवं समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर फाइलेरिया मुक्ति राष्ट्रीय अभियान और सहयोगी रेडियों 91.2 एफएम. थनोद का शुभारंभ किया। अभियान के दौरान मितानिन दीदियों द्वारा क्यूलेक्स, एडीज व एनोफ्लीज से बचाव एवं फ़ाइलेरिया को जड़ से हटाने के लिए कार्य किया जाएगा। श्री साहू ने इस दौरान मितानिन भवन के लिए 20 लाख रूपए की घोषणा करते हुए उन्हें उनके कार्यो की सराहना की।

सहयोगी रेडियों 91.2 एफएम. का उद्देश्य समुदाय की सक्रिय भागीदारी से स्थानीय भाषा एवं बोली में पंचायती राज, कृषि, पर्यावरण, संस्कृति, मौसम, शिक्षा, खेल, आजीविका, स्थानीय कार्यक्रमों व जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रसारण सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से एक साझा मंच की व्यवस्था करना है। इससे सामुदायिक रेडियो में श्रोताओं की सहभागिता एवं भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। रेडियो पर छत्तीसगढ़ी व हिन्दी भाषा में गोठ-बात, वार्ता, साक्षात्कार, फोन-इन, गीत-संगीत, कविता, कहानी, सफलता की कहानी, एकांकी, चौट शो, प्रश्न मंच, मन की बात, जिज्ञासा समाधान, आज का चिंतन, प्रेरक प्रसंग, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं समसामायिक सूचनाओं का प्रसारण होगा।

कार्यक्रम के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिन दीदियों को उनके उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया गया। मितानिन दीदी कुंती नेताम, पिपरछेड़ी को कैंसर को ठीक करने में मदद, दोनों पैरों का ऑपरेशन एवं रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल में कृत्रिम अंग लगवाने में मदद के लिए सम्मानित किया गया। मितानिन कुंती द्वारा एक 60 वर्षीय महिला जिनके आधार कार्ड में 30 वर्ष होने के कारण पेंशन नहीं मिल पा रहा था, उनका आधार कार्ड सुधरवाया गया एवं प्रसव के समय खून की कमी वाली एक महिला को अपने पति से खून डोनेट करवाया गया। इसी प्रकार मितानिन पिंककला देशमुख, थनौद द्वारा 23 वर्षीय किशोरी के स्तन कैंसर ऑपरेशन में सहयोग एवं 45 वर्षीय महिला को रोजगार गारंटी योजना तहत भुगतान की राशि दिलवाई गई। मितानिन जानकी सिंहा, बोरई द्वारा एक टीबी मरीज की मृत्यु पश्चात घर के अन्य सदस्यों की टीबी लक्षण की जांच करवाई गई। ज्योति गोस्वामी, नगपुरा द्वारा 6 वर्षीय बच्ची को सांप डसने पर बैगा इलाज से छुड़वाकर तत्काल जिला अस्पताल में इलाज दिलाया गया एवं मलेरिया की दो मरीजों का मेकाहारा में इलाज कराने में मदद व उनके घर के सदस्यों के लिए स्वयं भोजन की व्यवस्था की गई। लता साहू, खपरी ने एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिला की जिला अस्पताल दुर्ग में सुरक्षित प्रसव में मदद की एवं मानसिक रोगी का जिला अस्पताल में इलाज भी कराया। अंजनी देशमुख, खाड़ा ने बीपी मरीज को गंभीर स्थिति में पाए जाने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया एवं गांव की राशन दुकान से लोगो को अतिरिक्त चावल दिलवाने में मदद की। उर्वशी देशमुख, कुथरेल ने एक हितग्राही को पेंशन दिलाने में मदद की एवं एक कुष्ठ रोगी की जांच कराई। राधा शर्मा धनोरा ने एक महिला को हिंसा से बचाया एवं पड़ोसी से समझौता करवाया। गर्भवती महिला को पैसे देकर आर्थिक सहायता की।

निजी अस्पतालों से लौटाई गई गर्भवती महिला को जिला अस्पताल में मिला उपचार

कोण्डागांव। जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत बनजुगानी की गर्भवती शांति का कोण्डागांव के निजी अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा प्रसव के दौरान स्वास्थ्य बिगडऩे पर एक अन्य निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इसके बाद भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर अंतत: महिला को कोण्डागांव के कुछ जागरूक युवकों द्वारा उचित उपचार हेतु जिला अस्पताल में दाखिल करवाया है। जहां तेजी से शांति के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा हैं।

बनजुगानी ग्राम निवासी शांति कोर्राम पति चौबीस कोर्राम को प्रसव हेतु उसके परिजनों द्वारा स्थानीय निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। जहां 12 जून को सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा शांति ने बेटी को जन्म दिया। सिजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी करने के बाद उसे छुट्टी दे दी गयी थी। लेकिन लगभग सप्ताह भर पेट में दर्द की समस्या होने से उसे दोबारा कोण्डागांव के निजी अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों की सलाह पर 20 जून को उसका दोबारा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद भी पेट में दर्द ठीक न होने पर निजी अस्पताल ने मरीज को अन्य निजी अस्पताल को रिफर कर दिया।

जब अन्य निजी अस्पताल ने भी शांति को रेफर कर दिया तो इसकी जानकारी कोण्डागांव नगर के कुछ जागरूक युवकों को लगी उन्होंने तुरंत जिला अस्पताल में संपर्क करते हुए शांति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल करवाया है। जहां जिला अस्पताल में शांति का उपचार कर रहे डॉ एस नागुलन ने बताया कि उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आ रहा है। अब तक जिला अस्पताल में शांति का दो ऑपरेशन हो चुका है। उसे पूरी तरह से स्वस्थ होने में लगभग 8 से 10 महीने का समय लग सकता है।

जिला अस्पताल के लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ एस नागुलन ने बताया कि, शांति को गंभीर टीबी की बीमारी है। जिसके कारण सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान परेशानी हुई। शांति को उपचार के लिए मुंह के रास्ते गोली खिलाना अभी संभव नहीं है। कोशिश किया जा रहा है कि इंजेक्शन और लिक्विड के माध्यम से शांति का उपचार जल्द पूरा किया जाए। हालाकि डॉक्टरों ने भरोसा जताया है कि, शांति के स्वास्थ्य में जल्द सुधार आएगा।

सिस्टम पर बच्चों की स्ट्राइक, भोजन पानी के लिए छात्रों ने किया हाईवे जाम

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चों ने बुधवार को अंबिकापुर-बनारस नेशनल हाईवे जाम कर दिया। यह बच्चे लंबे समय से पेयजल और भोजन की समस्या से जूझ रहे हैं। अब अपनी मांगों को लेकर 10 किमी पैदल ही वाड्रफनगर पहुंच गए। सिस्टम पर बच्चों की इस स्ट्राइक के बाद अफसरों में हड़कंप मच गय। मौके पर पहुंचे अफसरों ने किसी तरह से बच्चों को समझाया और जाम खत्म कराया। इसके बाद स्कूल में पानी के लिए टैंकर और हैंडपंप खनन के लिए मशीन भेजी गई है।

अधीक्षक से शिकायत पर भी हल नहीं हुई

प्रदेश के पूर्व शिक्षामंत्री डा. प्रेमसाय सिंह के गृहक्षेत्र वाड्रफनगर अंतर्गत कोटराही एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चे लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी के साथ ही भोजन को लेकर बच्चे नाखुश थे। छात्रावास अधीक्षक से कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं हुआ, बल्कि छात्रावास अधीक्षक की लताड़ बच्चों को सुनने को मिली। इससे परेशान होकर बच्चे एकजुट होकर बुधवार को पैदल ही विद्यालय से वाड्रफनगर के लिए चल पड़े।

अधीक्षक को हटाने की मांग पर अड़े बच्चे

बच्चे 10 बजे वाड्रफनगर के राजीव चौक पहुंच गए और अंबिकापुर-बनारस मुख्यमार्ग पर चक्काजाम कर दिया। बच्चों द्वारा हाईवे पर चक्काजाम करने की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वाड्रफनगर तहसीलदार मोइनुद्दीन खान, बीईओ रोहित जायसवाल मौके पर पहुंचे। बच्चों की समस्या सुनने के बाद अधिकारियों ने बच्चों को समझाया। समस्याओं के निराकरण के आश्वासन के बाद भी काफी देर तक बच्चे विद्यालय के अधीक्षक को हटाने की मांग पर अड़े रहे।

नहीं थी समस्याओं की जानकारी-बीईओ

अधिकारियों ने किसी तरह समझाकर बच्चों का चक्काजाम 11 बजे समाप्त कराया और उन्हें वापस विद्यालय भेजा। वाड्रफनगर बीईओ रोहित जायसवाल ने बताया कि कोटराही एकलव्य आवासीय विद्यालय के समस्याओं की जानकारी अधीक्षक ने नहीं दी थी, जिसके कारण समस्याओं के निराकरण की पहल नहीं हो सकी थी। पेयजल की समस्या दूर करने के लिए पानी टंकी भेजी गई है और परिसर में बोर कराने मशीन भेजी जा रही है। अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए पहल की जाएगी।

चुनाव: नक्सली क्षेत्रों में रहेगी तगड़ी सुरक्षा

हैदराबाद में हुई अंतर्राज्यीय बैठक

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में आने वाले थाना प्रभारी और अधिकारियों की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। यह बैठक छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्रप्रदेश राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की उपस्थिति में आयोजित की गई। इस समन्वय बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नक्सल विरोधी अभियान, कानून व्यवस्था एवं अपराधिक गतिविधियों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। चारों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों द्वारा राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में अपेक्षित पुलिस बंदोबस्त, कानून व्यवस्था और नक्सल गतिविधियों से संबंधित विषयों पर प्रस्तुतीकरण की गई।

इस अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के साथ तेलंगाना पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार, महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ, आंध्रप्रदेश पुलिस महानिदेशक राजेंद्र नाथ रेड्डी, नक्सल अभियान छत्तीसगढ़ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा, बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, और तेलंगाना, महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रो में बेहतर तालमेल के साथ आगामी चुनाव को संपादित करने के लिए पुलिस थाना स्तर, जिला स्तर, रेंज स्तर व अंतर्राज्यीय स्तर की लगातार बैठक आयोजित की जा रही है। अंतर्राज्यीय समीक्षा बैठक के बाद ग्रेहाउंड प्रशिक्षण केंद्र में जाकर वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे डीआरजी, बस्तर फाइटर, कोबरा, सीआरपीएफ बलों के सभी सदस्यों से रूबरू होकर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

छत्तीसगढ़ में गोबर अब कचरा नहीं बल्कि कमाई का बना जरिया

धमतरी। छत्तीसगढ़ में गोबर अब कचरा या गंदगी नहीं, बल्कि कमाई का जरिया बन चुका है। प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना गोधन न्याय योजना से गौपालकों एवं किसानों के लिए गेमचेंजर साबित हो रही है। यहां के किसान गोबर बेचकर सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब गोबर बेचकर किसी ने पढ़ाई के लिए लैपटाप खरीदे, किसी ने खेतीबाड़ी के लिए पैसे जुटाए हैं तो किसी ने जमीन खरीदने का सपना पूरा किया।

इसी क्रम में गोधन न्याय योजना से धमतरी जिले के ग्राम पोटियाडीह के यादव परिवार के जीवन शैली में भी बदलाव आया। मोहित राम यादव ने बताया कि गोधन न्याय योजना शुरु होने से पहले घर के मवेशियों के गोबर का कोई हिसाब-किताब नहीं था, न ही गोबर एकत्र करने में कोई खास रुचि थी। गोबर को सिर्फ घुरवा में डाल दिया जाता था। मगर गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने से मवेशियों के गोबर का महत्व बढ़ गया है, अब वे गोबर गौठान में नियमित रूप से बेच रहे हैं और 15 दिवस के भीतर उनके बैंक खाते में पैसे भी आ रहे हैं। जिससे उनकी आमदनी अच्छी हो रही है एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। गोबर बेचकर उस राशि से जमीन खरीदने के सपने को पूरा कर लिया। अब उनकी खुद की जमीन हो गई है।

गोधन न्याय योजना से 03 लाख 58 हजार से ज्यादा किसानों को लाभ हो रहा है। 17 हजार 834 स्व-सहायता समूहों के 02 लाख 09 हजार 750 सदस्यों को इस योजना से आजीविका मिल रही है। इस योजना ने माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाकर उनका आत्मविश्वास मजबूत किया है। प्रदेश में 10 हजार 327 गौठान स्वीकृत किए गए है, जिनमें से 10 हजार 263 गौठानों को निर्माण पूरा हो चुका है। याने 99.38 प्रतिशत गौठानों का निर्माण कर लिया है। गौठानों द्वारा स्वयं की राशि से गोबर की खरीदी की जा रही है अभी तक 5 हजार 960 स्वावलंबी गौठानों द्वारा 66 करोड़ 96 लाख रुपए के गोबर की खरीदी की जा चुकी है। गोधन न्याय योजना मे अभी तक कुल 125.54 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। इसकी एवज में 251 करोड़ रुपए का भुगतान गोबर विक्रेताओं को किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

मिड डे मील खाकर बीरतराई के 14 बच्चे बीमार

कोरबा। करतला ब्लॉक के ग्राम बीरतराई में मध्यान्ह भोजन खाकर शासकीय मिडिल स्कूल के 14 बच्चे बीमार हो गए। उल्टी की शिकायत पर 8 छात्राओं को कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है। चिकित्सकों के देखरेख में सभी छात्राओं का इलाज जारी है। कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। मिड डे मील के तहत विद्यालय के बच्चों ने करील की सब्जी खाई थी। इस दौरान 8 विद्यार्थियों ने पेट, सिर में हल्का दर्द और उल्टी आने की बात कही। स्कूल के शिक्षकों ने तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र कोथारी में बच्चों को लाया। करील एक तरह की वनोपज है। बांस के पौधे से ही करील को निकाला जाता है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में सब्जी बनाकर इसका सेवन किया जाता है। 8 छात्राओं को एम्बुलेंस के जरिए कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अस्पताल में भर्ती 8 में से 7 ने मिड डे मील खाया था। एक छात्रा ने भोजन नहीं किया लेकिन वह कमजोरी महसूस कर रही थी।

दंतैल हाथी ने घर में सो रही महिला को कुचला

जशपुर। जशपुर के नारायणपुर वन परिक्षेत्र में घूम रहे एक दंतैल ने ग्राम गिधाबहार जामचुंआ में आकर तबाही मचा दी। गुस्सैल दंतैल ने घर में सो रही एक अधेड़ महिला को भी कुचलकर मार डाला। सूत्रों ने बताया कि जशपुर के नारायणपुर वनपरिक्षेत्र में इस समय हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। इसी दल का एक दंतैल अपने झुंड से बिछड़कर ग्राम गिधाबहार जामचुँआ पहुंच गया। अपनी झुंड से बिछड़ चुका यह दंतैल काफी गुस्से में था और उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी मकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। एक घर में घुसकर उसने सो रही एक अधेड़ महिला को भी कुचलकर मार डाला। सूत्रों की माने तो पिछले पखवाड़े भर से हाथियों का दल नारायणपुर वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है। उसने घर पर सो रही 45 वर्षीय महिला को कुचलकर मार डाला। बाहर खड़ी वाहन को भी नुकसान पहुंचाया। कुनकुरी रेंजर ने हादसे की पुष्टि करते हुए घटना की पुष्टि करते हुए ग्रामीणों को वन्यजीवों से दूर रहने की अपील की है।

जनता की मांगों के अनुसार विकास कार्य प्राथमिकता

धमतरी। धमतरी विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम धमतरी के अंतर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ताओं एवं निरंतर वार्ड वासियों के द्वारा अनेक बहुप्रतीक्षित मांगे विधायक के समक्ष रखी गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए विधायक ने अनेक वार्डों में निर्माण कार्यों की स्वीकृति कराई है, जिसके अंतर्गत नवागांव वार्ड में मुक्तिधाम का विकास एवं मरम्मत कार्य राशि 10 लाख, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वार्ड स्थित आमातालाब में घाट निर्माण कार्य राशि 03.99 लाख, सोरिद वार्ड में लिमाही तलाब में पचरी निर्माण कार्य राशि 03.49 लाख, रिसाई पारा पश्चिम वार्ड में हरप्रीत सिंह गिल घर से शिव टेलर तक सीसी रोड निर्माण कार्य राशि 1.07 लाख, महिमासागर वार्ड स्थित एकलव्य खेल मैदान में चेंजिंग रूम निर्माण कार्य राशि 1.45 लाख, महिमा सागर वार्ड स्थित एकलव्य खेल मैदान में वॉशरूम निर्माण कार्य राशि 1.55 लाख, रामपुर वार्ड में पूर्णिमा गुप्ता घर से रमेश हिरवानी घर होते हुए राजकुमार हीरवानी घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य राशि 3.33 लाख तथा आदि कार्यों की स्वीकृति मिली है।

डीजल चोरी पर रोक नहीं लगने पर दी आंदोलन की चेतावनी

कोरबा। बीएमएस के महामंत्री अशोक कुमार सूर्यवंशी ने एसईसीएल कुसमुंडा एरिया के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर खदान में बढ़ती डीजल चोरी पर रोक नहीं लगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। खदान की सुरक्षा में तैनात त्रिपुरा राइफल्स जवानों के डंपर ऑपरेटरों व भारी भरकम मशीनों के ऑपरेटरों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उन सबकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। बीएमएस के महामंत्री सूर्यवंशी ने कुसमुंडा खदान की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर डीजल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में बताया है कि खदान में डीजल चोरों के घुसने पर कर्मचारियों से भी अभद्र व्यवहार व मारपीट करते हैं। डंपर व भारी भरकम मशीनों को जबरन रोकवाकर धमकाया जाता है। असुरक्षा के बीच एसईसीएल कर्मचारी काम करने मजबूर हैं। खदान की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा त्रिपुरा राइफल्स के जवान संभाल रहे हैं, लेकिन डीजल चोरी पर अंकुश लगाने में असफल हो रहे हैं।

शिकायत पर निराकरण के लिये पहुंचे महापौर

कोरबा। वार्ड क्र. 14 झोपड़ीपारा व पम्प हाउस के एस.ई.सी.एल. कालोनी के नियमित किये जा रहे निरीक्षण की कड़ी में महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद अपने ही वार्ड 14 में पहुंचकर वार्डवासियों से बातचीत एवं गहन निरीक्षण पर पाया गया कि नालियों की सफाई के दौरान उनसे लगे स्लैब टूट गये हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है तथा बस्तियों में बनी कांक्रीट सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। भ्रमण के दौरान महापौर श्री प्रसाद ने वस्तुस्थिति देखकर साथ में आये निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि नाले-नालियों के ऊपर लगे स्लैब को जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें यथाशीघ्र नये स्लैब लगाकर उसे दुरूस्त करें तथा क्षतिग्रस्त सी.सी. रोड का प्राक्कलन बनाकर उसे बनाने अधिकारियों को निर्देशित किया। दूसरी ओर एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों से विगत दिनों वार्ड के भ्रमण के दौरान महापौर श्री प्रसाद ने एस.ई.सी.एल. कालोनी में जगह-जगह कचरे के ढेरनुमा बने अपशिष्ट पदार्थो के उचित प्रबंधन कर उन्हें साफ-सुथरा बनाये रखें।

धमतरी नगर निगम कॉम्प्लेक्स टेंडर का मामला गरमाया

■ **व्यवसाईयों ने दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन**

धमतरी । नगर निगम में इन दिनों अखाड़ा बना हुआ है। मामला नवनिर्मित व्यवसायी कॉम्प्लेक्स का है। जिसके दुकानों के आवंटन को लेकर व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम ने शहर के जालमपुर वार्ड, रामपुर वार्ड, और सदर उत्तर वार्ड में बने तीन कॉम्प्लेक्स की दुकानों के आवंटन के लिए निविदा निकाली थी। जिसमें धमतरी के करीब 200 व्यापारियों ने टेंडर भरा था। इस टेंडर को खोलने के लिए 25 जुलाई मंगलवार का दिन घोषित किया गया था। लेकिन इस तिथि को बिना किसी सूचना के आगे बढ़ा दिया गया।जिसके बाद टेंडर भरने वाले व्यापारियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाना शुरु किया।

नाराज व्यापारियों ने निगम दफ्तर के सामने बैठकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस मामले में नगर निगम की तरफ से जिम्मेदार अधिकारियों ने ठीक से जानकारी नहीं होने की बात कहकर मामला टाल दिया है। माना जा रहा है कि शहर के व्यापारी अब इस मुद्दे को लेकर न्यायालय का रुख करेंगे। जहां से वह पूरी टेंडर प्रक्रिया पर स्टे लगाने की मांग कर सकते हैं।

नगर निगम जालमपुर वार्ड, रामपुर वार्ड पानी टंकी के पास और सदर उत्तर में 13 दुकानों का निर्माण करेगी। जिसके लिए आवंटन की प्रक्रिया में धांधली बरतने का मामला सामने आया है। मंगलवार को निविदा खोलने की तिथि थी। लेकिन निविदा जमा करने की तिथि अचानक दो दिन और बढ़ा दी गई। जिसे लेकर आक्रोश है।

लोगों के मुताबिक निविदा में नागरिकों को आवेदन निविदा प्रपत्र 750 रुपए में खरीद कर दर प्रस्ताव 24 जुलाई शाम 5.30 बजे प्रस्तुत किया करना था। साथ ही 25 जुलाई को निविदा 11 बजे खोलने का तारीख रखा गया था। जिसके लिए निविदा में हिस्सा लेने वाले नागरिक व्यवसायी मंगलवार को निगम पहुंचे।लेकिन निविदा जमा करने की तिथि दो दिन आगे बढ़ा दी गई थी।

नरेंद्र रोहरा नेता प्रतिपक्ष ने कहा निगम ने बिना किसी सूचना के टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया।जिससे अब इस पूरे टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।बिना किसी सूचना के टेंडर को आगे बढ़ाना न्याय संगत नहीं है।

बीजेपी पार्षदों ने भ्रष्टाचार होने की संभावना जताते हुए आयुक्त विनय कुमार से नियत तिथि में ही निवेदन खोलने की बात कही और कारण पूछा। वहीं इस मामले में निगम के इंजीनियर ने संबंधित विभाग को आवेदन प्रेषित करने की बात कही है। इस अवसर पर पार्षद श्यामा साहू, बिसन निषाद, सरिता असाई, प्राची सोनी, हेमंत बंजारे, प्रकाश सिन्हा, , सुशीला तिवारी समेत कई व्यवसायी मौजूद थे।

भाजपा ने रायगढ़ नगर निगम का घेराव कर विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

रायगढ़। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आंदोलन का अभियान चलाया है।इसी कड़ी में रायगढ़ में प्रदर्शन हुआ।जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रायगढ़ नगर निगम का घेराव करते हुए,विधायक, महापौर और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर के विकास कार्यों के नाम पर कमीशनखोरी का आरोप के साथ ही सड़क, पानी, बिजली जैसी समस्या को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान महामंत्री ओपी चौधरी, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, रत्थू गुप्ता, विकास केडिया, सुनील रामदास अग्रवाल, सहित कई बीजेपी नेता मौजूद थे।

यह रैली दोपहर को बीजेपी दफ्तर से शुरु होकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए नगर निगम पहुंची।इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम दफ्तर में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर के विकास कार्यो में जमकर कमीशन खोरी की जा रही है।वार्डों में बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं के मामले में घोर अनियमितता बरती जा रही है। रायगढ़ नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ ही स्थानीय विधायक प्रकाश नायक बीजेपी कार्यकर्ताओं के निशाने पर थे।

अनुराग सिंहदेव ने कहा शहर के विकास कार्यो के लिये कोई काम नहीं हो रहे हैं। केवल कमीशनखोरी चल रही है। प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत निगम का घेराव किया गया है। मूलभूत समस्याओं को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है।

इस प्रदर्शन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम महापौर जानकी अमृत काटजू को निशाने पर लिया।साथ ही साथ स्थानीय विधायक प्रकाश नायक को निगम में हो रहे भ्रष्टाचार का जिम्मेदार माना। इस दौरान बीजेपी नेता विवेक रंजन सिन्हा ने विधायक प्रकाश नायक पर गंभीर आरोप लगाए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

दिल्ली अध्यादेश बिल सोमवार को अमित शाह करेंगे पेश

नईदिल्ली। दिल्ली अध्यादेश बिल सोमवार को लोकसभा में पेश होगा। मिली जानकारी के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह इसे सोमवार सुबह लोकसभा में पेश करेंगे। साथ ही जानकारी दे दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी। अब ऐसे में दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल सोमवार यानि 31 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के द्वारा इसका विरोध पुरजोर तरीके से चल रहा है। जानकारी यह भी हो कि दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश केंद्र सरकार के द्वारा 19 मई को जारी किया गया था। बता दें कि इस अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्रधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा, जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा।

अमित शाह के पत्र का खड़गे ने दिया जवाब

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस पत्र का जवाब दिया जिसमें उन्होंने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद में कांग्रेस और सभी दलों से सहयोग मांगा था। खड़गे ने अपने जवाब में लिखा कि इस पर प्रधानमंत्री द्वारा विपक्षी दलों को दिशाहीन बताना बेतुका ही नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से हम सदन में आकर मणिपुर पर बयान देने का आग्रह कर रहे हैं परंतु ऐसा लगता है कि उनका ऐसा करना उनके सम्मान को ठेस पहुँचाता है। हमारी इस देश की जनता के प्रति प्रतिबद्धता है और हम इसके लिए हर कीमत देंगे। वहीं, राज्यसभा में उन्होंने कहा कि मैं अपने मुद्दों को सदनों के सामने रख रहा था, और जब 50 लोगों ने 267 पर ध्यान दिया, तो मुझे सदन में बोलने का मौका भी नहीं मिला। ठीक है। लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया गया, ये मेरे विशेषाधिकार को धक्का है। ये मेरा अपमान हुआ है।

भारत जोड़ो यात्रा 2 की तैयारी यूपी पर कांग्रेस का फोकस

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 जल्द ही शुरू होने वाली है। इस यात्रा में उत्तर प्रदेश को अधिक तवज्जो दिए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश पर अधिक फोकस रखेगी। इस भारत जोड़ो यात्रा 2 के संयोजक दिग्विजय सिंह है जो यात्रा को लेकर रणनीति बना रहे है। ये यात्रा इतनी अहम इसलिए है क्योंकि विपक्षी मोर्चा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के गठन के बाद इसे निकाला जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि इस यात्रा में राहुल गांधी अकेले नहीं होंगे। इस बार उनके साथ विपक्षी मोर्चा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के साथी भी होंगे। इसमें कई नेताओं के नाम सामने आए हैं जो भारत जोड़ो यात्रा दो का हिस्सा हो सकते है। कांग्रेस इस यात्रा को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 12 सितंबर और गांधी जयंती 2 अक्टूबर से शुरू करने पर विचार कर रही है।

एनडीए की 3 पार्टियां, ईडी सीबीआई और आईटी : उद्धव

मुंबई। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में तीन मजबूत पार्टियां थीं। ठाकरे ने यह टिप्पणी शिवसेना (यूबीटी) पार्टी के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक और राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ एक साक्षात्कार में की। साक्षात्कार का पहला भाग बुधवार को सामना में प्रकाशित हुआ और पार्टी के सोशल मीडिया चैनलों पर प्रसारित हुआ। ठाकरे ने कहा कि कई वर्षों के बाद मुझे पता चला कि एनडीए नामक अमीबा अभी भी इस देश में जीवित है। देश के देशभक्त नेताओं के गठबंधन, जिसे भारत कहा जाता है, का मुकाबला करने के लिए हमारे प्रधान मंत्री ने अचानक 36 दलों (भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा) की बैठक बुलाई। दरअसल, उन्हें 36 पार्टियों की जरूरत नहीं है. वर्तमान में, एनडीए में तीन दल मजबूत हैं, जो ईडी, आयकर और सीबीआई हैं।

तेजस्वी के करीबी मंत्री का नीतीश ने पटला फैसला

पटना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक फैसले के बाद से एक बार फिर से महागठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं होने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में हुए 480 ट्रांसफर को रद्द कर दिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं राजद और खास करके तेजस्वी यादव को सख्त संदेश दे दिए है। दरअसल, बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजद कोटे के पास है। इसके मंत्री आलोक मेहता हैं जिन्हें तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है। आलोक मेहता ने ही वो ट्रांसफर के आदेश दिए थे जिसे नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया है। हालांकि इस को लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर किसी चीज के बारे में सूचना आई कि कुछ अधिकारियों का अनावश्यक तबादला हो गया है। इसके बाद विभाग और सब लोगों ने तय किया कि अभी इसे छोड़ देंगे।

मणिपुर को लेकर संसद में गतिरोध जारी

हंगामे के बीच कई विधेयक हुए पेश

नईदिल्ली। संसद के मानसून सत्र के पांचवें दिन भी हंगामा जबरदस्त तरीके से जारी रहा। हालांकि हंगामे के बीच ही संसद के दोनों सदनों में कामकाज जारी रहा। एक ओर जहां विपक्षी दल मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते रहे और उनका हंगामा जारी रहा तो वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से दोनों सदनों में कई विधेयक भी पेश किए गए हैं। साथ ही साथ पारित भी किए गए। लेकिन आज भी दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा। इन सब के बीच विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा खबर यह भी है कि दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में पेश कर सकते हैं।

लोकसभा की कार्यवाही

कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बुधवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जिस पर चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकृति प्रदान की। सदन में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई द्वारा पेश इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह सभी दलों के नेताओं से बातचीत करके इस पर चर्चा की तिथि के बारे में अवगत कराएंगे।

लोकसभा ने बुधवार को मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान और चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच 'वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023'को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया।

सरकार ने बुधवार को कहा कि इस साल एक अप्रैल तक केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के पास कुल 19,233 शिकायतें और अपीलें लंबित थीं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग में सूचना आयुक्तों के चार स्थान रिक्त हैं।

सदन में हंगामे के बीच ही सरकार ने छह विधेयक भी पेश किये। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023' पेश किया। गृह राज्य मंत्री राय ने 'जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023' और 'जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023' भी प्रस्तुत किये। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने 'संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023' और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने'संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023' सदन में शोर-शराबे के बीच ही पेश किये। कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 'खान और खनिज (विकास और नियमन) संशोधन विधेयक, 2023' पेश किया।

राज्यसभा की कार्यवाही

मणिपुर हिंसा पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा शुरू कराने की मांग को लेकर बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच राज्यसभा में तीखी नोकझोंक हुई। राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सदस्य अमी याग्निक एवं अन्य महिला नेताओं को चुनौती दी कि वे राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं बिहार में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार एवं बलात्कार की घटनाओं पर बोलने का साहस दिखाएं? अमी याग्निक ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न पूछते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से जानना चाहा कि वह और मंत्रिमंडल में उनकी महिला सहयोगी मणिपुर के मुद्दे पर कब बोलेंगी? इसके जवाब में स्मृति ने कहा कि वह इस बात पर घोर आपत्ति व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा कि न केवल महिला मंत्रियों बल्कि महिला राजनीतिक नेताओं को भी मणिपुर के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं बिहार में होने वाली घटनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मणिपुर हिंसा पर सरकार के रवैये तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संसद के भीतर कोई बयान नहीं दिये जाने के विरोध में विपक्षी दलों के सदस्यों के सदन से बर्हिगमन करने की घोषणा की। खरगे ने भोजनावकाश के बाद सदन की बैठक फिर शुरू होने पर आसन की अनुमति से अपनी बात रखते हुए कहा, '''इस सदन में हम (मणिपुर मुद्दे पर) जो चर्चा चाहते थे, उसके लिए हम प्रधानमंत्री के वक्तव्य की अपेक्षा कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा चर्चा की मांग करते हुए चार-पांच दिन हो गये है तथा प्रधानमंत्री संसद भवन में (अपने कक्ष में) आते हैं और उनके द्वारा की गयी मांग को (टीवी पर) देखते हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में लगभग 30,000 रिक्तियां भरी जा चुकी हैं। राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने शासन संबंधी कई सुधार किए हैं जिनमें भर्ती क्षेत्र भी शामिल है।

संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच होगी आरपार की लड़ाई

लोकसभा अध्यक्ष ने दी अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति

नईदिल्ली। मणिपुर वीडियो मामले को लेकर संसद में विपक्षी पार्टियों का हंगामा जारी है। विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के दोनों सदन में मणिपुर मामले पर जवाब दें। इसी मांग को लेकर विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है और आज संयुक्त विपक्ष इंडिया की तरफ से कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है, इस नोटिस पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी अनुमति दे दी है।

विपक्षी सदस्यों ने सदन में प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग की और खूब हल्ला किया। 'प्रधानमंत्री सदन में आओ' और 'वी वांट जस्टिस' जैसे नारे भी लगाये गये। विपक्ष की मांग है कि सरकार मणिपुर वीडियो मामले पर सदन में चर्चा कराये। सत्ता पक्ष भी लगातार यह कह रहा है कि वे सदन मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए माहौल बनाना होगा। 12 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति दे दी। प्रस्ताव पर पहले चर्चा होगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

बुधवार सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद कुछ देर का मौन रखा गया, उसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। कार्यवाही शुरू होने के महज 15 मिनट बाद ही कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। आज प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू भी नहीं हो पायी क्योंकि जैसे ही इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस और विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर के मुद्दे को उठाने लगे और नारेबाजी करने लगे।

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सदन में उनका अपमान हो रहा है। उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सदन में उनका माइक बंद कर दिया गया ताकि आवाज सुनी ना जा सके। यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि जनता का अपमान है। इधर राज्यसभा में भी मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू हुआ और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

कांग्रेस पार्टी की ओर से यह जानकारी दी गयी है कि अविश्वास प्रस्ताव सदन में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई पेश करेंगे। यह अविश्वास प्रस्ताव संयुक्त विपक्ष की सहमति से लाया जा रहा है। विपक्ष की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज नेता सोनिया गांधी भी सदन पहुंची हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार के अहंकार को तोड़ने और मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी को बोलने के लिए बाध्य करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद गौरव गोगोई असम के कालियाबोर सीट से सांसद हैं।

विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के सदस्यों की मंगलवार को बैठक हुई थी जिसमें मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में फैसला हुआ था।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत-पाकिस्तान मैच के शेड्यूल में हो सकता है बदलाव

नई दिल्ली। भारतीय टीम को इस साल के अंत में होने वाले वनडे विश्व कप में पाकिस्तान से भिड़ना है। दोनों टीमें 15 अक्तूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भले ही कार्यक्रम को पहले ही अंतिम रूप दे दिया हो और पिछले महीने सार्वजनिक कर दिया हो, लेकिन इस साल टूर्नामेंट के सबसे प्रतिष्ठित मुकाबले में से एक की तारीख में बदलाव की संभावना है।

भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले की तारीख बदली जा सकती है। दरअसल, जिस दिन दोनों टीमों के बीच यह महामुकाबला होने वाला है वह नवरात्रि का पहला दिन है। गुजरात में रात भर गरबा नृत्य के साथ इसे मनाया जाता है। एजेंसियों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बीसीसीआई को किसी अन्य तारीख पर मैच कराने की सलाह दी है। समाचार एजेंसी ने बताया कि यह मैच निर्धारित शेड्यूल से एक दिन पहले 14 अक्तूबर को हो सकता है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, चूंकि 15 अक्टूबर को नवरात्रि समारोह का पहला दिन है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने सलाह दी है कि इस मैच को पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके लिए सुरक्षा अधिकारियों की भारी तैनाती की भी आवश्यकता होगी। जरूरत पड़ने पर आईसीसी को तारीख में बदलाव पर फैसला लेने के लिए बीसीसीआई के साथ बैठना होगा। आईसीसी के करीबी सूत्रों ने कहा, आगे चर्चा की आवश्यकता है और जब भी संभव होगा हम किसी भी बदलाव की सलाह देंगे। बीसीसीआई भी सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर विचार कर रहा है और जल्द ही इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एजेंसियों ने बोर्ड से कहा है कि ऐसे मौके पर भारत बनाम पाकिस्तान जैसे हाई-प्रोफाइल मैच से बचना चाहिए। इस मैच के लिए हजारों प्रशंसक अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 344 अंक चढ़ा निफ्टी 17750 के पार

नई दिल्ली। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 351.49 (0.53%) अंकों की बढ़त के साथ 66,707.20 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी 97.70 (0.50%) अंक उछलकर 19,778.30 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को वोडफोन आइडिया के शेयर 15% जबकि पंजाब नेशन बैंक के शेयर चार प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में एफएमसीजी, रियल्टी और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के शेयरों ने दम दिखाया। इस दौरान एलएंडटी के शेयर तीन प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए।

307 फीसदी बढ़ा पंजाब नैशनल बैंक का मुनाफा

नईदिल्ली। पंजाब नैशनल बैंक ने बुधवार को जून 2023 को समाप्त तिमाही (पहली तिमाही 24) में अपने स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 307 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,255.4 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। बैंक ने पिछले साल की समान तिमाही में 308.4 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। इस तिमाही में मार्च तिमाही (वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही) के 1,158.61 करोड़ रुपये के मुकाबले नेट प्रॉफिट में 8.3 फीसदी का इजाफा हुआ। जून तिमाही में बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घटकर 7.73 प्रतिशत रह गई, जो पिछली तिमाही में 8.74 प्रतिशत थी। पिछले साल की जून तिमाही में जीएनपीए11.27 फीसदी था। जून तिमाही में पीएनबी का शुद्ध एनपीए भी घटकर 1.98 फीसदी रह गया, जो पिछली तिमाही में 2.72 फीसदी था।

तीन गुना बढ़ेगा तेल कंपनियों का ऑपरेटिंग मुनाफा

नईदिल्ली। घरेलू बाजार में ऊंचे खुदरा मूल्य और विदेशी बाजारों में कच्चे तेल के दाम कमोबेश निचले स्तर पर रहने से पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों को चालू वित्त वर्ष में कम-से-कम एक लाख करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ हासिल होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। चालू वित्त वर्ष में अबतक कच्चे तेल की कीमत एक साल पहले की तुलना में 30 प्रतिशत से अधिक नीचे आ चुकी है। वहीं पेट्रोलियम कंपनियों ने इस दौरान दाम नहीं घटाए हैं। तेल कीमतों में मई, 2022 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्रिसिल ने बुधवार को जारी एक नोट में कहा कि चालू वित्त वर्ष में पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियां एक लाख करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा सकती हैं। वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान पेट्रोलियम कंपनियों का औसत परिचालन लाभ 60,000 करोड़ रुपये रहा था। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में तो यह 33,000 करोड़ रुपये के निचले स्तर पर आ गया था।

कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी खरीद सकती है रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी

नईदिल्ली। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जल्द ही रिलायंस रिटेल वेंचर्स में हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही है। फाइनैंशियल टाइम्स ने बुधवार को बताया कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एक फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 1 अरब डॉलर के निवेश पर विचार कर रही है। अगर कंपनी हिस्सेदारी खरीदती है तो इससे मुकेश अंबानी की रिटेल यूनिट का मूल्यांकन 100 अरब डॉलर हो जाएगा। यह ऐसे समय में हो रहा है जब कई गल्फ वेल्थ फंड भारत के रिटेल मार्केट में हिस्सेदारी पाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 में, सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट फंड ने 462.4 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर 2.04 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिलायंस रिटेल में 1.3 अरब डॉलर का निवेश किया था।

पूंजी बाजार में बढ़ रहा विदेशी निवेश

प्रह्लाद सबनानी

किसी भी देश के लिए स्टॉक (पूंजी) बाजार में हो रहा उतार-चढ़ाव उस देश की अर्थव्यवस्था में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। यदि स्टॉक बाजार में तेजी दिखाई देती है तो इसका आशय सामान्यत: यह लगाया जाता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार दृष्टिगोचर है। इसके विपरीत यदि स्टॉक बाजार नीचे की ओर जाता दिखाई देता है तो इसका आशय यह लगाया जाता है कि निकट भविष्य में उस देश की अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याएं आने वाली हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में आज लगभग किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जिसके चलते भारत का स्टॉक बाजार नित नई ऊंचाईयां हासिल करता दिखाई दे रहा है। इसके ठीक विपरीत अमेरिका, चीन, रूस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, आदि जैसे लगभग सभी विकसित देशों में आज आर्थिक समस्याओं का अंबार लगा है। मुद्रास्फीति की समस्या को तो कई विकसित देश अभी भी सम्हाल नहीं पाए हैं। विदेशी निवेशक संस्थानों का भरोसा इसी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर वापस बहाल हुआ है और औसतन प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए के शेयर विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय स्टॉक बाजार में खरीद रहे हैं।

वर्ष 2014 के बाद से भारतीय स्टॉक बाजार ने जो रफ्तार पकड़ी हैं, वह भारतीय स्टॉक बाजार के इतिहास में पहिले कभी भी नहीं रही है। 7 अप्रैल 2014 को भारत में सेन्सेक्स 22,343 अंकों पर था, जो 26 मई 2014 को 24,700 के आंकड़े को पार कर गया। वर्ष 2019 में चुनावी बिगुल बजने से पहले 10 अप्रैल 2019 को सेन्सेक्स 38,600 अंकों पर पहुंचा। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्टॉक बाजार ने लगभग 73

प्रतिशत यानी 16,250 अंको से ज्यादा की छलांग लगाई। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी पर नियंत्रण स्थापित करते हुए भारत ने पूरी दुनिया के पटल पर सफलता की एक कहानी लिखी। वर्ष 2020 में भारतीय स्टॉक बाजार ने दुनिया के बाजारों के मुकाबले निवेशकों को 15 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न प्रदान किया। मौजूदा समय में भारत में सेन्सेक्स 65,000 के पार पहुंच गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सेन्सेक्स ने 66 प्रतिशत यानी 25,500 अंकों की तेजी दिखाई है। बम्बई स्टॉक एक्स्चेंज का मार्केट केप 7 अप्रैल 2014 को 74.51 लाख करोड़ रुपए था, जो वर्तमान में बढ़कर 294.11 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है।

भारतीय स्टॉक बाजार में वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के दौरान विदेशी निवेशकों की अहम भूमिका रही है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश भारतीय स्टॉक बाजार में किया है। अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1500-1600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश भारतीय स्टॉक बाजार में किया है। जो विदेशी संस्थागत निवेशक जनवरी-फरवरी 2023 में भारतीय कम्पनियों के शेयर बेचकर चीन की कम्पनियों के शेयर खरीद रहे थे परंतु अब मार्च-अप्रैल 2023 के बाद से पुन: वे भारतीय कम्पनियों के शेयर खरीदने लगे हैं। पिछले 9 वर्षों में से केवल 2 वर्ष ही ऐसे रहे हैं जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारतीय स्टॉक बाजार में शुद्ध रूप से निवेश ऋणात्मक रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशक आज भारतीय स्टॉक बाजार की ओर इतना अधिक आकर्षित क्यों हो रहे हैं। एक तो भारतीय स्टॉक बाजार ने अपने निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न प्रदान किए हैं। जब हम इस रिटर्न की तुलना अन्य देशों के पूंजी बाजार से करते हैं तो ध्यान में आता है कि विश्व के अन्य कई देशों के स्टॉक बाजार में निवेश पर लगभग 8-9 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है, जबकि भारतीय स्टॉक बाजार में निवेश पर लगभग 15-16 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है। इसी प्रकार, अमेरिका में बांड्ज में निवेश पर केवल 2-3 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है और भारत में बैंक में सावधि जमाराशि पर लगभग 6 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है, ऋण, कामर्शियल पेपर, बांड्ज आदि पर भी लगभग 6 से 7.5 प्रतिशत तक रिटर्न मिलता है।

क्रमश: ...

कानून के हाथ मजबूत करने की तैयारी

आशीष कुमार अंशु

केंद्र सरकार 129 साल पुराने जेल कानून को बदल रही है। गृह मंत्रालय के अनुसार प्रिजन एक्ट 1894 को बदल कर मॉडल प्रीजन्स एक्ट 2023 को लाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। इस नए कानून को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस नए एक्ट को जेल सुधार पर केन्द्रित किया गया है, जिसमें कैदियों के पुनर्वास से लेकर उन्हें मिलने वाले पैरोल और फर्लो जैसे विषय शामिल हैं। जेलों के आधुनिकीकरण से लेकर तकनीकी के माध्यम से कैदियों को अधिक सुरक्षित वातावरण दिए जाने की भी चर्चा है। हाल के दिनों में देखा गया है कि जेलों के अंदर हिंसक घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेल के अंदर दिल्ली के एक गैंगस्टर की हत्या, उसके प्रतिद्वन्दी गैंग ने कर दी। जब वे हत्याकांड को अंजाम दे रहे थे, सीसीटीवी की फुटेज में दिखाई पड़ता है कि तिहाड़ के सुरक्षाकर्मी वहीं खड़े होकर यह सब देखते रहे। इतना ही नहीं, कई शातिर अपराधी जेल के अंदर से ही अपना सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं। बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री जब घोटाले के मामले में जेल के अंदर थे, उन दिनों भी उनका ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट अपडेट हो रहा था। जेल के अंदर बैठे अपराधी को पुलिस का भय नहीं है। एक ठग सुकेश ने जेल में रहते हुए बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को जेल के अंदर मिलने के लिए बुला लिया। वह जेल के अंदर बैठकर देश की प्रतिष्ठित मॉडलों से ना सिर्फ बात कर रहा था बल्कि उन्हें उपहार भी भिजवा रहा था। एक अन्य गैंगस्टर ने एक टीवी चैनल को जेल में बैठकर साक्षात्कार देते हुए अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जेल में बैठे यह खतरनाक अपराधी किस तरह देश की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या और जेलों के अंदर बढ़ते गैंगवार को देखते हुए मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 बनाने की घोषणा हुई है। नए प्रिजन एक्ट में महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों को लेकर भी विशेष प्रावधान होगा। जेल से मिलने वाली छुट्टी फरलो है। आम तौर पर फरलो लेकर कैदी पारिवारिक समारोह, किसी की अंतिम क्रिया कर्म अथवा अपने सगे संबंधी की बीमारी पर, उनसे मिलने के लिए जाता है। बंदियों को लेकर इस तरह की खबर समाचार पत्रों में आती रहती है। वर्तमान नियम के अनुसार एक वर्ष में कोई कैदी अधिकतम तीन बार फरलो ले सकता है। फरलो की अधिकतम अवधि 14 दिनों की है। आम तौर पर कैदी को यह अपने परिवार और समाज से मेल जोल बढ़ाने के लिए मिलता है। वहीं परोल लेने के लिए कारण बताना जरूरी होता है जबकि पैरोल की अवधि एक महीने तक बढ़ाई जा सकती है। जेलों के अंदर होने वाली हिंसा को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी संशंकित है। पिछले साल उसने गृह मंत्रालय को यह सुझाव भेजा था कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की जेलों में बंद खूंखार अपराधियों की निशानदेही करके उन्हें दक्षिण भारत की अलग अलग जेलों में भेज दिया जाए। एनआईए ने ऐसे 25 खूंखार गैंग का जिक्र किया था, जिन्हें दूसरे राज्यों की जेलों में भेजा जाना बहुत जरूरी है। यदि वे उत्तर भारत की जेलों में रहे तो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके वे लगातार एक दूसरे गैंग के लोगों का खून बहाते रहेंगे। उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र से अलग थलग किए बिना यह खूनी संघर्ष नहीं रूकने वाला। पुणे की एक ऐतिहासिक घटना के अनुसार, वहां की औंध रियासत के राजा ने एक आयरिश मनोवैज्ञानिक को जेल में बंद दुर्दांत अपराधियों को खुली जेल में रखकर उन पर प्रयोग करने की सुविधा दी थी। यह अपराधी को जेल से छूटने के बाद पुन: अपराधी बनने से रोकने में कारगर भूमिका निभा सकता है।

संसदीय लोकतंत्र पर सवाल

ललित गर्ग

भारत की संसदीय प्रणाली दुनिया में लोकप्रिय एवं आदर्श है, बावजूद इसके सत्ता की आकांक्षा एवं राजनीतिक मतभेदों के चलते लगातार संसदीय प्रणाली को धुंधलाने की घटनाएं होते रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब संसद की कार्रवाई को बाधित करना एवं संसदीय गतिरोध आमबात हो गयी है। न केवल संसद बल्कि राज्यों की विधानसभाओं में समुचित रूप से विधायी कार्य न हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद एवं विधानसभाएं ऐसे मंच हैं जहां विरोधी पक्ष के सांसद एवं विधायक आलोचना एवं विरोध प्रकट करने के लिये स्वतंत्र होते हैं, लेकिन विरोध प्रकट करने का असंसदीय एवं आक्रामक तरीका, सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच तकरार और इन स्थितियों से उत्पन्न संसदीय गतिरोध लोकतंत्र की गरिमा को धुंधलाने वाले हैं। अपने विरोध को विराट बनाने के लिये सार्थक बहस की बजाय शोर-शराबा और नारेबाजी की स्थितियां कैसे लोकतांत्रिक कही जा सकती है?

दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की विधायिकाओं में जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, वे सचमुच चिंताजनक हैं। हालत यह है कि हंगामे व शोर-शराबों के दौर में न संसद का सत्र चल पा रहा है और न ही राज्यों की विधानसभाएं। संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक तस्वीर एक जैसी सामने आ रही है। राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अमर्यादित आचरण के आरोप में पूरे सत्र के लिए, तो राजस्थान में भी तीन दिन पहले तक मंत्री रहे राजेन्द्र गुढ़ा और विपक्षी दल भाजपा के विधायक मदन दिलावर को शेष सत्र के लिए निलम्बित कर दिया गया। संसद में हुड़दंग मचाने, अभद्रता प्रदर्शित करने एवं हिंसक घटनाओं को बल देने के परिदृश्य बार-बार उपस्थित होते रहना भारतीय लोकतंत्र की गरिमा से खिलवाड़ ही माना जायेगा। सफल लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष के साथ ही मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होती है। लेकिन पक्ष एवं विपक्ष दोनों ही लोकतंत्र को दूषित करने में लगे हैं।

यह देखना दुखद, दयनीय और शर्मनाक है कि मणिपुर को लेकर देश-दुनिया में तो चर्चा हो रही है, लेकिन भारत की संसद में नहीं। यह चर्चा न हो पाने के लिए जिम्मेदार है क्षुद्र राजनीति और एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने की प्रवृत्ति। संसद के तीन दिन बर्बाद हो गए, लेकिन मणिपुर पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। विपक्ष गृहमंत्री से

पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहता है। यह जिद चर्चा से बचने का बहाना ही अधिक जान पड़ती है, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना पर पहले ही बोल चुके हैं और दूसरे, सत्तापक्ष की ओर से यह नहीं कहा गया कि वह आगे इस विषय पर कुछ नहीं कहने वाले। लेकिन विपक्ष ने ठान लिया है कि वही होना चाहिए, जो उसकी ओर से कहा जा रहा है। जबकि सत्तापक्ष की ओर से बार-बार यह कहा जा रहा है कि मणिपुर सहित अन्य जरूरी मुद्दों पर यदि चर्चा के लिए समय कम पड़ा और उसे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो यह काम किया जा सकता है, इससे यही प्रतीत होता है कि विपक्ष संसद में ऐसा माहौल बना देना चाहता है कि आम जनता को लगे कि सरकार मणिपुर पर चर्चा करने से बच रही है। शायद इसीलिए विपक्षी नेता संसद परिसर में प्रदर्शन करने और दोनों सदनों में नारेबाजी को अतिरिक्त प्राथमिकता दे रहे हैं। लगभग ऐसी ही स्थितियां मध्य प्रदेश और राजस्थान की विधानसभाओं में देखने को मिल रही हैं।

मध्यप्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में चार माह बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्यप्रदेश में तो विधानसभा के आखिरी सत्र में पांच बैठकें होनी थीं लेकिन शोर-शराबे के हालात ऐसे रहे कि दो बैठकों के बाद ही मानसून सत्र समाप्त कर दिया गया। वैसे तो यह कोई नई बात नहीं है। देश की अधिकांश विधानसभाएं हंगामे और शोरगुल में ही डूबी रहती हैं, बिना कामकाज किये सम्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या यह सबसे बड़े लोकतंत्र की निशानी है? राजनीतिक दल और राजनेता यह अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की संसद और विधानसभाएं राजनीति करने का मंच नहीं हैं। कानून बनाने, विकास की योजनाओं को लागू करने और उनको मजबूती देने के साथ जनसमस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान निकालने के लिए बने लोकतंत्र के ये पवित्र मंदिर हैं। सत्तारुढ़ दल और विपक्षी दल एक-दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में रहते हैं और इसी में सदनों का कीमती समय एवं जनता की गाढ़ी कमाई के अरबों रुपए हर साल खर्च एवं बर्बाद हो जाता है। जनता के पैसे से ही विधायक-सांसदों के वेतन-भत्ते और सुविधाएं उठाने वाले जनप्रतिनिधि उसी जनता की आवाज सदन में नहीं उठाएं तो क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं?

कितना दुखद प्रतीत होता है जब कई-कई दिन संसद में ढंग से काम नहीं हो पाता है। विवादों का ऐसा सिलसिला खड़ा कर दिया जाता है कि संसद में सारी शालीनता एवं मर्यादा को ताक पर रख दिया जाता है। विवाद तो संसद में भी होते हैं और सड़क पर भी। लेकिन संसद को सड़क तो नहीं बनने दिया जा सकता? वैसे, भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसे अवसर बार-बार आते हैं, जब परस्पर संघर्ष के तत्व ज्यादा और समन्वय एवं सौहार्द की कोशिशें बहुत कम नजर आती है। स्पष्ट है कि यदि दोनों पक्ष अपने-अपने रवैये पर अडिग रहते हैं तो संसद का चलना मुश्किल ही होगा। यदि वह चलती भी है, चर्चा होती है तो भी लगता नहीं कि वह स्तरीय और देश को आश्वस्त करने वाली होगी, क्योंकि सभी राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ की रोटियां सेंकने के फेर में दिख रहे हैं। फिर विधानसभा चुनाव एवं आम चुनाव सामने होने की वजह से सभी कोई एक-दूसरे पर दोषारोपण कर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगाने में चाहे जितनी ऊर्जा खपाएं, वे देश को निराश करने का ही काम कर रहे हैं। वास्तव में संसद में गंभीरता जताने के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वह किसी तमाशे से कम नहीं। यह तमाशा देश को लज्जित एवं शर्मसार करने वाला है।

आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह- इसी से भारतीय राजनीति ग्रस्त हैं, ऐसे राजनेता गिनती के मिलेंगे जो इन तीनों स्थितियों से बाहर निकलकर जी रहे हैं। पर जब हम आज राष्ट्र की विधायी संचालन में लगे अगुओं को देखते हैं तो किसी को इनसे मुक्त नहीं पाते। आजादी के अमृतकाल तक पहुंचने के बावजूद लोकतंत्र के सारथियों में परिपक्वता नहीं पनप पा रही हैं, साफ चरित्र जन्म नहीं ले पाया है, लोकतंत्र को हांकने के लिये हम प्रशिक्षित नहीं हो पाये हैं। उसका बीजवपन नहीं हुआ या खाद-पानी का सिंचन नहीं हुआ। आज आग्रह पल रहे हैं- पूर्वाग्रहित के बिना कोई विचार अभिव्यक्ति नहीं और कभी निजी और कभी दलगत स्वार्थ के लिए दुराग्रही हो जाते हैं। कल्पना सभी रामराज्य की करते हैं पर रचा रहे हैं महाभारत।

विपक्षी दल अनावश्यक आक्रामकता का परिचय देंगे तो सरकार उन्हें उसी की भाषा में जवाब देगी- कैसे संसदीय गरिमा कायम हो सकेगी? इसका सीधा मतलब है कि संसद में विधायी कामकाज कम, हल्ला-गुल्ला ज्यादा होता रहेगा। कायदे से इस अप्रिय स्थिति से बचा जाना चाहिए। यह एक बड़ा सच है कि संसदीय प्रक्रिया एक जटिल व्यवस्था है और इसे बार-बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लोकतंत्र पहले भी बड़ी परीक्षाओं से गुजरकर निखरा है और लोगों को यही उम्मीद है कि अमृतकाल में भारतीय लोकतंत्र को हांकने वाले लोग परिवक्व होंगे, भारतीय लोकतंत्र इन दुर्भाग्यपूर्ण एवं विडम्बनापूर्ण त्रासदियों से बाहर आयेगा। संसदीय लोकतंत्र की अपनी मर्यादाएं हैं, वह पक्ष-विपक्ष की शर्तों से नहीं, आपसी समझबूझ, मूल्यों एवं आपसी सहमति की राजनीति से चलता है। एक तरह से साबित हो गया, भारतीय राजनीति में परस्पर विरोध कितना जड़ एवं अव्यावहारिक है। राजनीति की रफ्तार तेज है, लेकिन कहीं ठहरकर सोचना भी चाहिए कि लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभाओं में थोड़ा सा समय विरोध-प्रतिरोध के लिए हो और ज्यादा से ज्यादा समय देश एवं प्रांतों के तेज विकास एवं देश निर्माण की चर्चाओं एवं योजनाओं में लगें।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

दक्षिणामूर्युपनिषद् (भाग-4)

गतांक से आगे...

भगवद् दर्शन के लिए ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य की आवश्यकता है। इसके आते ही अज्ञानान्धकार समाप्त होकर आत्मारूपी दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठता है। अपने ज्ञानरूपी दण्ड से वैराग्य रूपी अरणी में मन्थन (चिन्तन) करके अज्ञानान्धकार के समापन के लिए गूढ़ अर्थ अर्थात् परमतत्त्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। उस परमतत्त्व का दर्शन, निरन्तर ज्ञान और वैराग्य के परिपालन एवं चिन्तन से ही सम्भव हैं। परमतत्त्व के बारे में चिन्तन न करना ही पाश है, उक्त पाश से बँधे हुए द्वैतवाद से भयभीत व्याकुल, मोहरूपी शनि अर्थात् मृत्यु के मुँह में गये हुए विवेक रूप मार्कण्डेय को परमतत्त्व का चिन्तन फिर से जीवन दान करते हुए अर्थात् आत्म-तत्त्व का बोध कराते हुए परमात्मा के परम आनन्द (अपने स्वरूप) में स्थित कर देता है।

ब्रह्म को प्रकाशित करने वाली तत्त्वज्ञान रूपिणी बुद्धि को ही दक्षिणा कहा है, वही ब्रह्म साक्षात्कार के लिए द्वार अर्थात् मुँह है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानियों ने उसी को दक्षिणामुख नामक शिव कहा है। सृष्टि के आदि में प्रजापति ब्रह्माजी ने इनकी ही उपासना की। उसी से शक्ति प्राप्त करके सृष्टि की रचना रूपी अपने मनोरथ को पूर्ण किया और प्रसन्न हुए, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा ही इनके उपासक हैं। इस शिवतत्त्वरूपी गुप्त विद्या का जो पाठ करता है, वह समस्त कल्मषी से छूट जाता है एवं इसको अच्छी तरह से जानने तथा मनन, चिन्तन करने वाला मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसी यह उपनिषद् है।

मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

ब्रह्मानंद राजपूत

भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने जमीन से जुड़े रहकर ''जनता के राष्ट्रपति'' के रूप में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनायी थी। एक ऐसे इंसान जो बच्चे, युवाओं, बुजुर्गों सभी के बीच में लोकप्रिय थे। देश का हर युवा, बच्चा उन्हें अपना आदर्श मानता था, आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रत्येक वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानते है तभी वो डॉ. कलाम जैसे महान वैज्ञानिक के आदर्शों और पद-चिन्हों पर चलकर चंद्रयान-2 का सफल प्रक्षेपण कर पाए।

डॉ. कलाम के बतौर परियोजना निदेशक रहते देश का पहला स्वदेशी उपग्रह एसएलवी-3 जुलाई 1980 को लांच किया था। इस लांचर के माध्यम से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। डॉ कलाम ने कई साल इसरो में परियोजना निदेशक के रूप में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को काफी आगे बढ़ाया। डॉ. कलाम अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को दिया करते थे। वे कहते थे कि माँ ने उन्हें अच्छे-बुरे को समझने की शिक्षा प्रदान की। उनका कहना था कि अगर उनकी जिन्दगी में माँ नहीं होती तो वो इतना सफल कभी नहीं बन पाते। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफी कुछ डॉ. कलाम को जाता है। डॉ. कलाम ने त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी ताकतवर मिसालें बनायीं। डॉ. कलाम ने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम को काफी ऊंचाइयों तक पहुँचाया।

डॉ. कलाम सहित देश के महान वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बदौलत ही देश इसरो की स्थापना के दो दशकों के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन सका। डॉ. कलाम 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। डॉ. कलाम कि देखरेख में ही भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और भारत देश परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को देश के प्रति उनके योगदान के लिए 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न प्रदान किया। इसके बाद डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम 2002-

2007 तक देश के राष्ट्रपति रहे।

बतौर शिक्षक डॉ. कलाम अपने स्टूडेंट्स को सच्ची लगन से पढ़ाते थे। वे चाहते थे कि लोग उन्हें शिक्षक के रूप में अधिक जानें। आपको पता ही होगा कि अपने अंतिम समय 27 जुलाई, 2015 को भी डॉ. कलाम शिलॉन्ग के आईआईएम कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। लेक्चर में उन्होंने कुछ ही शब्द बोले थे कि दिल का दौरा पड़ने के कारण उन्हें चक्कर आ गया। तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया किन्तु बचाया नहीं जा सका। वे 84 वर्ष के थे।

हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का सम्पूर्ण जीवन देशसेवा में बीता। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी को साल 2002 में सर्वसम्मति से पक्ष और विपक्ष की प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस सहित दर्जनों दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया। डॉ. कलाम को राष्ट्रपति बनाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी के पास प्रस्ताव लेकर गए, जिसका उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन किया। नतीजतन देश की प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस सहित दर्जनों दलों ने एकमत से डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी का नामांकन कराया और नतीजों में भी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी 90 प्रतिशत के आसपास मतों से जीतकर देश के 11वें राष्ट्रपति बने और पूरे पांच साल उनका कार्यकाल शानदार रहा। इसके बाद डॉ. कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर व भारतीय विज्ञान संस्थान,बैंगलोर के मानद फैलो, व एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। राष्ट्रपति कार्यालय से मुक्ति के बाद डॉ. कलाम अंतिम सांस तक शिक्षक की भूमिका में रहे।

इंडिया बनाने में जुटे अखिलेश के घर में सेंध

अनिल सिंह

उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की सियासी रणनीति पर भाजपा की सेंधमारी भारी पड़ रही है। एक तरफ विपक्षी दल एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को हराने के अभियान में जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ उनके अपने नेता पराये हो रहे हैं। भाजपा ने सपा, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं को अपने पाले में लाकर कांग्रेसनीत गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। इस पालाबदल का असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ेगा। सपा के कई ऐसे नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है, जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत है।

विपक्षी दल मजबूत गठबंधन बनाकर भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन अपने घर को ही नहीं बचा पा रहे हैं। विपक्षी दलों में हो रही इस भगदड़ का लाभ भाजपा को चुनावी माहौल बनाने में मिलेगा। सोमवार को लखनऊ में सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद के कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ले ली। सबसे ज्यादा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है। उसके ग्यारह कद्दावर नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। बसपा के पांच तथा रालोद और कांग्रेस के एक-एक नेता ने भाजपा की सदस्यता ली।

दरअसल, भाजपा का पूरा फोकस पिछड़े वर्ग पर है। वह पिछड़े वोटरों को अपने खेमे में करने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है और दूसरे दलों के पिछड़े वर्ग के नेताओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार एवं कायस्थ वोटर उनको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पिछड़ों के पास सपा, रालोद जैसे विकल्प हैं, लिहाजा इन वर्गों को जोड़ने से उसे दोहरा लाभ मिलेगा।

भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में सबसे चौंकाने वाला नाम वाराणसी सीट से 2019 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी शालिनी यादव का है। शालिनी को अखिलेश यादव का नजदीकी माना जाता था, इसलिये उनका पार्टी छोड़ना सपा के लिए बड़ा झटका है। शालिनी चंदौली जिले के कद्दावर कांग्रेसी नेता राज्यसभा के उपसभापति तथा केंद्रीय मंत्री रहे दिवंगत श्याम लाल यादव की पुत्रवधु हैं। उन्होंने 2017 में कांग्रेस से बनारस के मेयर का चुनाव लड़ा था। कांग्रेस लंबे अर्से बाद दूसरे नंबर पर रही थी।

शालिनी यादव की जमीनी पकड़ और लोकप्रियता को देखते हुए ही अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल करके बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतारा था। शालिनी दूसरे नंबर पर रहीं, जबकि कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं कोलअसला से तीन बार विधायक रह चुके अजय राय की जमानत तक जब्त हो गई थी। शालिनी के भाजपा में आने से बनारस के साथ पड़ोसी जिले चंदौली में भी पार्टी को मजबूती मिलेगी। शालिनी का परिवार मूलरूप से चंदौली जिले का ही रहने वाला है।

शालिनी के अलावा समाजवादी पार्टी छोड़ने वालों में पूर्व मंत्री सहारनपुर के साहब सिंह सैनी, पूर्व मंत्री जौनपुर के जगदीश सोनकर, हरदोई के पूर्व सांसद अंशुल वर्मा, जौनपुर की पूर्व विधायक सुषमा पटेल, जौनपुर से ही पूर्व विधायक गुलाब सरोज, हमीरपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा, हापुड़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यपाल यादव, हापुड़ से ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी सत्यपाल की पत्नी सुनीता यादव, हापुड़ के सिंभावली से ब्लॉक प्रमुख शालिनी यादव तथा बनारस के पूर्व जिलाध्यक्ष पीयूष यादव शामिल हैं।

साहब सिंह सैनी की सहारनपुर और मुरादाबाद में सैनी वोटों पर अच्छी पकड़ है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद से ही भाजपा की नजर दूसरे दलों के सैनी नेताओं पर थी। धर्म सिंह सैनी ने जब भाजपा छोड़ी थी, तब भाजपा ने इसकी भरपायी के लिए कांग्रेस नेता एवं विधायक नरेश सैनी को अपने खेमे में लाकर बेहट सीट से लड़ाया था, लेकिन नरेश जीत नहीं पाये। सपा की सरकार नहीं बनने के बाद धर्म सिंह फिर से भाजपा में लौटने का प्रयास कर रहे थे।

खतौली उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य एवं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने धर्म सिंह सैनी की वापसी का रोड मैप भी बना दिया था, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग को टाल दिया था। अब साहब सिंह सैनी के साथ भाजपा ने रालोद के दिग्गज नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी को अपने खेमे में लाकर पश्चिम में सैनी वोटों के बिखराव को रोक दिया है। राजपाल सैनी की मुजफ्फरनगर में सैनी वोटों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है।

पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर के भाजपा में शामिल होने पर जौनपुर में भी सपा को बड़ा झटका लगा है। मछलीशहर एवं शाहगंज सीट से चार बार विधायक रहे जगदीश सोनकर जमीन से जुड़े जुझारू नेता माने जाते हैं। रागिनी सोनकर के आने के बाद जगदीश के विकल्प सपा में सीमित हो गये थे। जगदीश के साथ ही मुंगराबादशाहपुर की पूर्व विधायक सुषमा पटेल एवं केराकत के पूर्व विधायक गुलाब सरोज ने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया है। इन तीनों पूर्व विधायकों के आने से भाजपा की रेड जोन वाली जौनपुर सीट ग्रीन जोन में बदल सकती है।

बसपा छोड़ने वाले नेताओं में आगरा में जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन गंगाधर कुशवाहा, आगरा से बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे रवि भारद्वाज, हमीरपुर के तिंदवारी विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे दिलीप सिंह, सीतापुर के सिधौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र पासी तथा मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे शिवान सैनी शामिल हैं। बसपा नेताओं के अलावा कांग्रेस के पूर्व मीडिया चेयरमैन राजीव बक्शी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है।

दरअसल, 2024 के सियासी समर में उतरने से पहले भाजपा विरोधी खेमे में हलचल पैदा करने की कोशिश कर रही है। दूसरे दलों के कद्दावर पिछड़े नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर उसके पक्ष में माहौल तो बनेगा। साथ ही, पिछड़ों का विश्वास जमने के बाद भाजपा को यूपी तथा केंद्र की सत्ता से हटा पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि सवर्ण वोटरों को यह लगने लगा है कि भाजपा उनके वोट को अपनी जेब में मानकर चल रही है और पार्टी नेताओं को उनकी कोई परवाह नहीं है। इस कारण सवर्ण जातियों का भाजपा से मोहभंग होने लगा है, लेकिन इसका पार्टी को कितना नुकसान होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

बापू की दिनचर्या

उपवास

बापू के उपवासों का ऐतिहासिक महत्त्व है। भारत में वे उपवास के मूर्धन्य आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुल मिलाकर सत्रह उपवास किए, जिनमें इक्कीस-इक्कीस दिनों के कई उपवास सम्मिलित हैं। उपवास बापू के रक्त में घुला मिला था। इसे उन्होंने अपनी माता के दूध से प्राप्त किया था। उनकी ही भाँति भय एवं विपत्ति में, रोग तथा व्याधि में-उपवास से ही वे सुख और शांति प्राप्त करते। उपवास से घबराने के वे विरुद्ध थे। इसे वे यम-नियम का अंग बताते। साथ ही वे इसे बड़े आध्यात्मिक प्रयत्न से उपार्जित अधिकार तथा सत्य एवं अहिंसा के पुजारी के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र मानते। इसीलिए खास अवसरों पर और बहुत सावधानी के साथ इसका वे प्रयोग करते। हर व्यक्ति निश्चित रूप से इस अस्त्र का उपयोग नहीं कर सकता। बापू आध्यात्मिक दृष्टि से ही इसका उपयोग करते। इससे सामान्यत: उनके स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुँचती । वे वृद्धावस्था में भी उपवास करना कठिन नहीं मानते। कहते कि आध्यात्मिक दृष्टि से किए जानेवाले उपवास को सहन करने में कठिनाई होती ही नहीं। शरीर क्षीण होगा ही, क्योंकि उसकी चरबी घटती है। पं. हरिभाऊ उपाध्यायजी ने एक बार कहा था कि बापू को उपवास से कोई आँच नहीं आती। यद्यपि उनका शरीर कमजोर हो जाता, तथापि उसमें इतनी सात्विक शक्ति संचित रहती कि उनका बाल बाँका नहीं हो पाता। दूसरे भोगी लोग अधिक खाते और अधिक गँवाते हैं, योगी थोड़ा खाते और अधिक संचित करते हैं। बापू अपनी इंद्रियों द्वारा जितनी शक्ति ग्रहण करते, उससे बहुत कम खर्च करते। अत: उनकी पूंजी बहुत थी। साधारण भोगी जहाँ एक ही उपवास में ढीला-ढाला हो जाता, वहाँ बापू-जैसे योगी कई उपवासों को सहन करने की शक्ति नहीं गंवाते बल्कि उलटा अधिक प्राप्त करते। अत: हमें उनके विषय में चिंतित होकर हतबुद्धि होने की आवश्यकता नहीं रहती। एक प्रसंग सन् 1914 का द. अफ्रीका का है। वहाँ चौदह दिन का अपना लंबा उपवास तोड़ने के छठे दिन बापू मि. कलनबक को लेने फिनिक्स आश्रम से फिनिक्स स्टेशन पैदल गए और उन्होंने कलनबक को आश्चर्यचकित कर दिया।

क्रमश: ...

तीसरी बार भी बनेगी हमारी सरकार, पीएम बोले- ये मोदी की गारंटी टॉप-3 में होगी भारतीय अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आईईसीसी) परिसर को देश को समर्पित किया है। बता दें कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का नाम भारत मंडपम रखा गया है।

इस अवसर पर पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर-भारत मंडपम में स्मारक टिकट और सिक्के जारी किए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मंडपम को देखकर हर भारतीय आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम भारत के सामर्थ्य और नई उर्जा का आह्वान है। भारत मंडपम भारत की भव्यता और इच्छाशक्ति का दर्शन है।

ये मोदी की गारंटी टॉप-3 में होगी भारतीय अर्थव्यवस्था

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, ये

मोदी की गारंटी है। उन्होंने आगे कहा कि आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। हमारे पहले कार्यकाल की शुरुआत में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 10वें स्थान पर था। दूसरे कार्यकाल में आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे कार्यकाल में दुनिया की पहली तीन अर्थव्यवस्थाओं में एक नाम भारत का होगा।पीएम मोदी ने कहा कि एक अद्भुत दृश्य मेरे सामने है। भव्य है, विराट है, विहंगम है। आज का ये जो अवसर है, इसके पीछे जो कल्पना है और आज हमारी आंखों के सामने उस सपने को साकार होते हुए हम देख रहे हैं, तब मुझे एक प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां गुनगुनाने का मन कर रहा है।

पीएम ने कारगिल युद्ध के शहीदों को किया याद

इस दौरान प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध के शहीदों को भी याद किया। पीएम ने कहा कि आज का दिन हर देशवासी के लिए ऐतिहासिक है। आज कारगिल विजय दिवस है। देश के दुश्मनों ने जो दुस्साहस दिखाया था उसे मां भारती के बेटे-बेटियों ने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया था। कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येक वीर को मैं पूरे राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज दुनिया यह स्वीकार कर रही है कि भारत %लोकतंत्र की जननी है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष होने पर %अमृत महोत्सव% मना रहे हैं, यह %भारत मंडपम% हम भारतीयों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया एक खूबसूरत उपहार है। कुछ हफ्तों बाद यहां ज्ञ-20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते कदम और भारत का बढ़ता कद इस %भारत मंडपम% से पूरी दुनिया देखेगी।

विपक्ष पर भी बरसे पीएम मोदी

इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस निर्माण को रोकने के लिए नकारात्मक सोच वालों ने क्या-क्या कोशिशें नहीं की, अदालतों के चक्कर काटे थे। कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने, टोकने की। जब कर्तव्य पथ पर बन रहा था तो न जाने क्या-क्या कथाएं चल रही थीं। अखबार, ब्रेकिंग न्यूज में न जाने क्या-क्या चल रहा था। कर्तव्य पथ बनने के बाद वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे कि अच्छा हुआ है। इस दौरान %भारत मंडपम% में सांस्कृतिक प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया।

भारत बना रहा है रूसी एस-400 और अमेरिकी पैट्रियट के टक्कर का मिसाइल डिफेंस सिस्टम

- चीन और पाक से लगती सीमा पर होगी तैनाती

नई दिल्ली। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए लगातार प्रयास कर रहा भारत अब एक ऐसा हथियार विकसित कर रहा है जिसके बारे में जानने के बाद चीन और पाकिस्तान जैसे देश कोई दुस्साहस करने से पहले सौ बार सोचेंगे। दरअसल भारत स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएएम) रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है जो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगी।

एएनआई ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि तीन-स्तरीय लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में उन्नत चरण में है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की परियोजना है।

स्वदेशी एलआरएसएएम रक्षा प्रणाली विकसित करने के बाद भारत हवा में ही दुश्मन के ड्रोन और लड़ाकू विमानों को निशाना बना पाएगा। इस तरह की तकनीकी क्षमता दुनिया के केवल चुनिंदा देशों के पास ही है। लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए भारत अब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहा है। हाल ही में भारत ने रूस से एस-400 वायु रक्षा

प्रणाली खरीदी थी। लेकिन अब जल्द ही भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद की लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इस मिसाइल प्रणाली का विकास तब हो रहा है जब भारत ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली एमआरएसएएम विकसित करने के लिए इजराइल से हाथ मिलाया है। एमआरएसएएम प्रणाली 70 से अधिक किलोमीटर तक हवाई लक्ष्य पर हमला कर सकती है। फिलहाल भारत जो एलआरएसएएम रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है वह रूस के एस-400 और अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बराबर होगी। पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद इसे चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। इस खास हथियार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) विकसित कर रहा है।

लालू के दबाव में झुके नीतीश, किया बोर्ड निगमों का पुनर्गठन

पटना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोर्ड- निगमों का पुनर्गठन करना पड़ गया। जबकि बिहार में एनडीए के साथ सत्तासीन होने के बाद नीतीश कुमार ने कभी भी बोर्ड-निगमों में भाजपा की हिस्सेदारी पर ध्यान नही दिया था। लेकिन राजद के साथ तालमेल करने के बाद उन्होंने राज्य के सभी बोर्ड-निगमों को पुनर्गठन कर दिया है और राजद को अनुपातिक हिस्सेदारी भी देना शुरू कर दिया है।

इसी कड़ी में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड में भोला यादव के अतिरिक्त 9 अन्य लोगों को भी बोर्ड में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसमें विनय कुमार चौधरी, ललित नारायण मंडल, प्रेम चंद्र मिश्रा, आचार्य सिया राम प्रसाद यादव, नारायण महतो, चितरंजन गगन, मदन शर्मा, रामाशीष यादव और प्रतिमा कुमारी हैं। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन तीन वर्षों के लिए किया गया है।

इसके साथ ही महिला आयोग, ओबीसी-ईबीसी आयोग, मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड के अलावा तमाम निगम, बोर्ड, आयोग को पुनर्गठन किया गया है। इसमें मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष जदयू नेता और नीतीश के भरोसेमंद कहे जाने वाले पूर्व एमएलसी सलीम परवेज को बनाया गया है। इसके अलावा विधानसभा और विधानपरिषद के कई सदस्य को इसमें सदस्य बनाया गया है।

सलीम परवेज बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति भी रह चुके हैं। मदरसा बोर्ड में महबूब आलम, सैयद रूकनुद्दीन अहमद और खालिद अनवर को सदस्य बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार देर रात तक इसी कार्य में लगे थे। कुछ विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है, जिसके बाद शेष कर रहें हैं। बता दें कि बिहार में बोर्ड और निगम का विघटन काफी दिन पहले हुआ था। एनडीए सरकार में भी बोर्ड और निगम का गठन नहीं हो सका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोर्ड और निगम को काफी दिन बाद पुनर्गठन किया गया है। बिहार में महिला आयोग जैसा अति संवेदनशील आयोग कार्यकारी के सहारे चल रहा था। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बीच कई दौर की बैठक के बाद बोर्ड और निगमों के पुनर्गठन करने पर फैसला लिया गया है।

स्मृति ने कांग्रेस नेताओं को राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार की महिला उत्पीड़न पर बोलने की चुनौती दी

कांग्रेस नेता के वहां जाने के बाद मणिपुर जलने लगा : ईरानी

नईदिल्ली। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं को बड़ी चुनौती दे डाली है। राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस सदस्य अमी याग्निक एवं अन्य महिला नेताओं को चुनौती दी कि वे राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं बिहार में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार एवं बलात्कार की घटनाओं पर बोलने का साहस दिखाएं?

अमी याग्निक ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न पूछते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से जानना चाहा कि वह और मंत्रिमंडल में उनकी महिला सहयोगी मणिपुर के मुद्दे पर कब बोलेंगी? इसके जवाब में स्मृति ने कहा कि वह इस बात पर घोर आपत्ति व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा कि न केवल महिला मंत्रियों बल्कि महिला राजनीतिक नेताओं को भी मणिपुर के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं बिहार में होने वाली घटनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या वह (कांग्रेस सदस्य याग्निक) इन राज्यों में महिलाओं पर हुए अत्याचार की घटनाओं पर बोलने का माद्दा रखती है?

केंद्रीय मंत्री ने कहा, क्या आपके भीतर माद्दा एवं साहस है कि आप छत्तीसगढ़ के बारे में बोलें?

क्या आपमें साहस है कि आप राजस्थान के बारे में बोले? क्या आपमें साहस है कि आप बिहार के बारे में बोलें? क्या आपमें साहस है कि आप लाल डायरी के बारे में बोलें? उन्होंने सवाल किया कि उनमें इस बारे में बात करने का साहस कब होगा कि एक कांग्रेस नेता के वहां जाने के बाद मणिपुर जलने लगा। स्मृति ने कहा, क्या आपमें इतना साहस है कि आप कांग्रेस शासित राज्यों में होने वाली बलात्कार की घटनाओं के बारे में बोलें? उन्होंने कांग्रेस सदस्य को नसीहत दी कि यदि वह इन घटनाओं पर नहीं बोल सकतीं तो उन्हें केंद्र की महिला मंत्रियों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए।

ज्ञानवापी केस में इलाहबाद हाईकोर्ट का सीधा आदेश

- 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करे एएसआई , ढांचे को नहीं हो कोई नुकसान

लखनऊ। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दूसरे दिन सुनवाई हुई। मुख्य न्यायधीश की बेंच में हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि अगर हिंदू पक्ष के मुताबिक ये सर्वे हुआ तो मस्जिद की पूरी इमारत खत्म हो जाएगी। वहीं हिंदू पक्ष ने इस बात से इनकार किया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद इलाहबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 31 जुलाई तक एएसआई का सर्वे पूरा हो। कोर्ट ने कहा कि बिना ढांचे को नुकसान पहुंचाए सर्वे हो। आज शाम पांच बजे तक ही सर्वे पर रोक लगी थी। एएसआई सर्वे के फैसले को हिंदू पक्ष एक जीत के तौर पर देखेगा। एएसआई सर्वे नहीं करे इसी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार तमाम अदालतों का दरवाजा खटखटाता रहा है। लेकिन अब सीधे हाई कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश आ गया है।

इससे पहले यूनियन ऑफ इंडिया/एएसआई इस मामले में पेश हुआ। उनका कहना है कि वह इस मामले में अपनी दलीलों सहित एक हलफनामा दाखिल कर रही है। वरिष्ठ वकील नकवी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 24 जुलाई के आदेश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने सुप्रीम कोर्ट के 24 जुलाई के आदेश की एक प्रति के साथ-साथ वाराणसी कोर्ट के 21 जुलाई के आदेश (एएसआई सर्वेक्षण के लिए) की एक प्रति मांगी है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन से पूछा कि क्या आप वाराणसी कोर्ट के 21 जुलाई के आदेश से संतुष्ट हैं? जैन ने हां में जवाब दिया। फिर मुख्य न्यायाधीश ने एएसआई के अधिकारी को डायस पर बुलाया।

जेडीएस-भाजपा गठबंधन पर पिता-बेटे में रार

कुमार स्वामी और एचडी देवगौड़ा ने चुनी अलग राह

बेंगलुरु। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक चहल पहल देखने को मिल रही है। वहीं इस वर्ष के अंत तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने तय है। इससे पहले मई में ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए हैं जहां जनता दल (सेक्युलर) को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी थी। इस हार के बाद पार्टी के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है।

अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर संभावना थी कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में जनता दल (सेक्युलर) शामिल हो सकती है। इन अटकलों को पार्टी अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने ही झुठला दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने मंगलवार को लोकसभा चुनावों को लेकर बडा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता दल (सेक्युलर) लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। गौरतलब है कि

एचडी देवेगौड़ा का ये बयान उनके बेटे कुमारस्वामी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी, जद(एस) और भाजपा विपक्ष के रूप में सहयोग करेंगे। दोनों नेताओं के इन विराधोभासी बयानों के बाद माना जा रहा है कि पिता-पुत्र के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहे है।

इस संबंध में बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं साफ तौर पर बता रहा हूं कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे है। लोकसभा चुनाव हमें अकेले लड़ेंगे। हमारी पार्टी चाहे तो पांच सीटें जीते या छह या एक। हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम उन सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे जहां हमारी स्थिति मजबूत है।

बता दें कि हाल ही में एचडी देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी ने बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर मिलकर काम करेगी। बीते दिनों बीजेपी ने 10 विधायकों को निष्कासित किया था। तब भी जनता दल (सेक्युलर) के विधायकों ने भाजपा का समर्थन किया था। विधानसभा से सभी विधायकों ने बायकॉट किया था।

जानकारों का कहना है कि पार्टी को लेकर चल रहे इस अंर्तविरोध को संक्रमण काल कहा जा सकता है। एक तरफ 94 वर्षीय एचडी देवेगौड़ा जेडीएस में काफी कम नियंत्रण मिल रहा है। दूसरी ओर पार्टी में बेटे कुमारस्वामी की पकड़ मजबूत हो रही है। सत्ता परिवर्तन होते हुए अब पार्टी की कमान धीरे धीरे कुमारस्वामी के पास जा रही है। बीते कुछ वर्षों में पार्टी के अधिकांश फैसले कुमारस्वामी ने ही किए थे।

लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी

सीआईसी के पास 19,000 से अधिक शिकायतें और अपीलें लंबित

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि इस साल एक अप्रैल तक केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के पास कुल 19,233 शिकायतें और अपील लंबित थीं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से लोकसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में कहा गया कि पारदर्शिता निगरानी संस्था में चार सूचना आयुक्तों के पद रिक्त थे, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 10 है। उन्होंने कहा कि 2021-22 की अवधि में 29213, 2020-21 में 38116, 2019-20 में 35138 और 2018-19 में 29655 मामले लंबित थे।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 12 (3) के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की ऐसी संख्या होगी, जो दस से अधिक नहीं होगी, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है। सिंह ने कहा, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा चार सूचना आयुक्त सीआईसी में पद पर हैं। मंत्री ने कहा कि आरटीआई कानून की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोगों में सूचना आयुक्तों की रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों का विषय है।

सिंह ने कहा कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण और दिशा-निर्देश जारी करना शामिल है, ताकि वे सूचना की आपूर्ति कर सकें या प्रथम अपील का प्रभावी ढंग से निपटारा कर सकें, जिसके परिणामस्वरूप सूचना आयोग में अपीलों की संख्या कम हो। उन्होंने कहा कि जहां तक दूसरी अपील का सवाल है, सीआईसी ने आरटीआई अधिनियम की प्रभावशीलता में सुधार के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि दूसरी अपील/शिकायतों की जल्द सुनवाई के लिए ई-कोर्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।

चुनाव से पहले मध्यप्रदेश में हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस

भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पवित्र नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की हिंदुत्व साख की चमक को कांग्रेस की ओर से कुछ हद तक कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। नदी, जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं और भगवान शिव से जुड़ी हैं, के संरक्षण को लेकर कांग्रेस भाजपा को विफल बता रही है। सत्तारूढ़ भाजपा की कथित विफलता पर प्रकाश डालते हुए, कांग्रेस नियमित नर्मदा आरती (प्रार्थना समारोह) भी आयोजित करेगी और नदी के किनारे घाटों (नदी तक जाने वाली सीढ़ियाँ) को साफ करेगी। इसे चुनाव से भी जोड़ कर देखा जा रहा है जिससे कांग्रेस को हिन्दू वोट मिलने की उम्मीद है।

नर्मदा सेवा सेना के बैनर तले, पार्टी मध्य प्रदेश में नदी के उद्गम स्थल अनुपपुर जिले के अमरकंटक और बड़वानी और अलीराजपुर जिलों में निकास बिंदुओं के बीच नदी के 1,077 किलोमीटर के क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्थानीय समितियों का गठन करेगी। विशेषज्ञों की मदद से, सेना विभिन्न हिस्सों में नदी के पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करेगी और उन स्थानों की पहचान करेगी जहां पानी नहाने और पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। विभिन्न बिंदुओं की भी पहचान की जाएगी जहां नदी में सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाहित होता है और फिर कांग्रेस इस प्रथा को समाप्त करने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार पर दबाव बनाएगी। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी बड़े पैमाने पर रेत खनन का मुद्दा उठाएगी, और कहा कि ये कारक नदी और इसकी जलीय संपदा को गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। विधानसभा चुनाव होने में चार महीने से भी कम समय बचा है, विपक्षी दल राज्य के सभी 52 जिलों और 230 विधानसभा क्षेत्रों में रामायण, भगवद गीता और शिव पुराण का पाठ करने की भी योजना बना रहा है। राज्य में कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर चलती हुई दिखाई दे रही है।

हार तय है, फिर भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया विपक्ष

नईदिल्ली। क्या विपक्ष प्रधानमंत्री की बात मानता है? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में विपक्ष को शुभकामना दी थी कि वह 2023 में भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये। इसलिए अब जब विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है तो प्रधानमंत्री का पुराना भाषण वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकृति दे दी है। विपक्षी गठबंधन (इंडिया) के घटक दलों की मंगलवार को हुई बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में फैसला हुआ था। बुधवार को जब लोकसभा का सत्र आरंभ हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का समय तय किया जायेगा। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के अलावा तेलंगाना की सत्तारुढ़ पार्टी बीआरएस ने भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था।

इस बीच, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्षी दलों की योजना के बीच 2018 में इस तरह के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जवाब सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित हो रहा है जिसमें उन्होंने विपक्ष का उपहास करते हुए कहा था कि उन्हें 2023 में भी ऐसा ही प्रस्ताव लाने की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने लोकसभा में 2018 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा था, ''मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करें कि 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का आपको मौका मिले।''

अस्थिरता फैलाती है कांग्रेस!

इसके अलावा कांग्रेस किस तरह अविश्वास प्रस्ताव के जरिये देश में अस्थिरता फैलाने का प्रयास करती है।

इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण भी खूब वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस ने हमेशा से अविश्वास प्रस्ताव की संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवेगौड़ा तथा कई अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों का उदाहरण देते हुए कहा था कि कैसे कांग्रेस ने सरकारों को गिराकर देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा किया।

हारी हुई लड़ाई क्यों लड़ रहा है विपक्ष?

हम आपको बता दें कि विपक्षी दलों के प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव का संख्याबल के लिहाज से विफल होना तय है लेकिन उनकी दलील है कि वे चर्चा के दौरान मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरकर 'अवधारणा' बनाने की लड़ाई जीत जाएंगे। विपक्षी दलों ने दलील दी है कि यह मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संसद में बोलने के लिए विवश करने की रणनीति भी है। दरअसल सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि मणिपुर की स्थिति पर चर्चा का जवाब केवल केंद्रीय गृह मंत्री देंगे। मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर संसद के भीतर बयान देने का दबाव बनाने के कई विकल्पों पर विचार करने के बाद यह फैसला किया गया कि अविश्वास प्रस्ताव ही सबसे कारगर रास्ता होगा, जिसके जरिये सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विवश किया जा सकेगा।

कांग्रेस का कहना है कि पूरे देश का ध्यान मणिपुर पर ''अविश्वास प्रस्ताव'' पर होगा और इससे अवधारणा के खेल में विपक्ष को मदद मिल सकती है। हालांकि देखा जाये तो अविश्वास प्रस्ताव का भविष्य पहले से तय है क्योंकि संख्याबल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में है और विपक्षी समूह के निचले सदन में 150 से कम सदस्य हैं।

सपने में मेहंदी लगाने का मतलब होता है बेहद खास

समझें जल्द आपके घर बजेगी शहनाई

स्वप्न शास्त्र में सपनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें अच्छे और बुरे सभी सपनों का मतलब बताया गया है। सपने आगामी जीवन के संकेत होते हैं। अच्छे सपने जीवन में

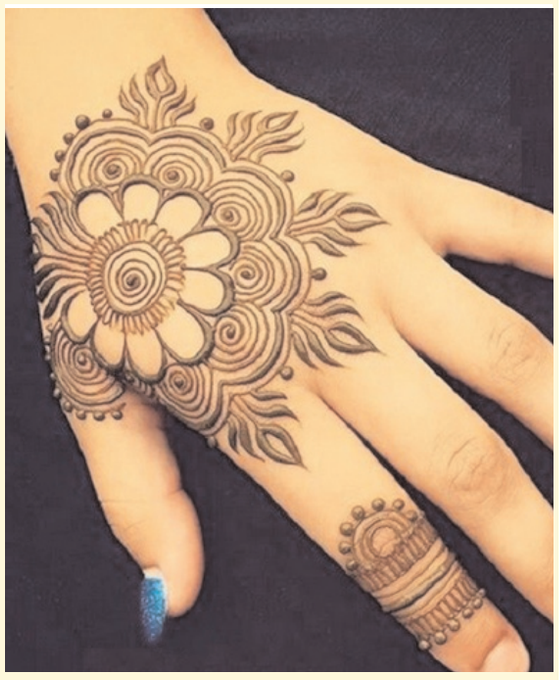

खुशियां लेकर आते हैं, तो बुरे सपने खतरे के संकेत होते हैं। कई सपने ऐसे भी होते हैं, जो शीघ्र शादी के संकेत होते हैं। खासकर, सपने में खुद को श्रृंगार करते देखना विवाह के संकेत होते हैं। वहीं, सपने में मेहंदी लगाने का मतलब भी बेहद खास होता है। आइए जानते हैं-

-सपने में खुद को श्रृंगार करते हुए देखना बेहद शुभ होता है। इस सपने का मलतब होता है कि जल्द आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इन खुशियों में आपकी शादी भी शामिल है। आसान शब्दों में कहें तो सपने में श्रृंगार करते हुए देखना शीघ्र विवाह के संकेत हैं।

-स्वप्न शास्त्र की मानें तो सपने में किसी महिला को सजी हुई देखना भी शुभ होता है। अगर महिला गहना पहनी हैं, तो और ज्यादा शुभ होता है। इस सपने का मतलब होता है कि आपकी शीघ्र शादी होगी। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, तो लव मैरिज के भी योग हैं। पुरुषों के लिए भी ये सपने विवाह के संकेत हैं।

-शुभ अवसर पर महिलाएं अपनी हाथों में मेहंदी लगाती हैं। अगर आप सपने में खुद अपने हाथों में मेहंदी लगा रही हैं या किसी महिला के हाथों में मेहंदी लगी हैं, तो इसका मतलब यह है कि जल्द आपके घर शहनाई बजने वाली है। पुरुष भी ये सपने देखते हैं, तो उनकी शादी के योग बनते हैं।

-सपने में मांग में सिंदूर लगाने का मतलब बेहद खास होता है। इस सपने का मतलब होता है कि जीवन में आने वाली बाधा दूर हो चुकी है। साथ ही सौभाग्य का आगमन होने वाला है।

-सपने में अविवाहित लड़की को श्रृंगार करते हुए देखना भी बेहद शुभ होता है। इस सपने का मतलब यह है कि जल्द आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं।

आर्थिक तंगी से पाना चाहते हैं छुटकारा तो जरूर करें ये उपाय

धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा-उपासना करने से काल, कष्ट, दुख और संकट सभी दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन में मंगल का आगमन होता है। ज्योतिषियों की मानें तो हनुमान जी की पूजा करने से शनि का प्रभाव भी क्षीण हो जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति पर शनिदेव की भी कृपा बरसती है।

मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान की पूजा उपासना की जाती है। इन्हें बजरंगबली, केसरी नंदन, शंकर सुवन, पवन पुत्र आदि नामों से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख और समृद्धि आती है। वहीं, शनि की बाधा भी दूर होती है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन ये उपाय जरूर करें। आइए जानते हैं-

-अगर आप आर्थिक तंगी समेत अन्य परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर उनके चरणों के समक्ष चमेली के तेल का दीप जलाएं। साथ ही उन्हें चमेली के तेल और सिंदूर का लेप लगाएं। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्या दूर होती है।

-अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं। अथक प्रयास के बावजूद काम बिगड़ रहे हैं, तो मंगलवार के दिन पूजा घर में हनुमान यंत्र की स्थापना करें। इसके पश्चात, विधि पूर्वक पूजा उपासना करें। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान यंत्र की पूजा करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं।

-हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है। अत: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग के फूलों की माला अर्पित करें। आप चाहे तो हनुमान जी को लाल गुलाब भी अर्पित कर सकते हैं। इससे हनुमान जी जल्द प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को करने से शनि की बाधा से मुक्ति मिलती है।

-अगर आप आर्थिक परेशानी से निजात पाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करें। वहीं, शाम में देसी घी के दीपक जलाएं। इसके पश्चात, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से समस्त दुखों का नाश होता है।

पाना चाहते हैं शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति

हिंदी पंचांग के अनुसार, चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार साल 2023 में 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के अनन्य और परम भक्त हनुमान की पूजा उपासना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा-उपासना करने से काल, कष्ट, दुख और संकट सभी दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन में मंगल का आगमन होता है। ज्योतिषियों की मानें तो हनुमान जी की पूजा करने से शनि का प्रभाव भी क्षीण हो जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति पर शनिदेव की भी कृपा बरसती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को साढ़ेसाती और शनि की ढैया की बाधा से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी साढ़ेसाती और शनि की ढैया से पीड़ित हैं, तो हनुमान जयंती के दिन ये उपाय जरूर करें। आइए जानते हैं-

- ज्योतिषियों की मानें तो वर्तमान समय में मकर, कुंभ और मीन राशि पर साढ़ेसाती चल रही है। वहीं, तुला और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। मकर राशि के जातकों पर साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है। वहीं, कुंभ राशि के जातकों पर दूसरा चरण चल रहा है। जबकि, मीन राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का प्रथम चरण चल रहा है। इसके अलावा, तुला और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। साढ़ेसाती लगने से मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानी होती है। व्यापार में नुकसान होता है। परिवार में कलह की स्थिति बनी रहती है। साथ ही शादी विवाह में भी बाधा आती है। अगर आपकी राशि भी इनमें एक है, तो हनुमान जयंती के दिन ये उपाय जरूर करें।
- शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जयंती के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन कर और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उनकी कृपा से समस्त दुखों का नाश होता है।
- हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को कुमकुम और नारियल अर्पित करें। वहीं, हनुमान के चरणों में अर्पित सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं।
- शनि की साढ़ेसाती और ढैया से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जयंती के दिन पूजा के समय चमेली या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से शनि की बाधा दूर होती है।

हनुमान जयंती पर करें ये खास उपाय

हनुमान जयंती का पर्व 6 अप्रैल को देशभर में किया जाएगा। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा और उपाय करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आरोग्य जीवन का वरदान देते हैं। हनुमान जयंती के दिन हनुमान मंदिर में जाकर भगवान को लाल रंग का सिंदूर, लड्डू अर्पित करने चाहिए। कुछ लोग गुड़ और चना भी अर्पित करते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा से विभिन्न ग्रहों की शांति भी होती है। खासकर मंगल ग्रह से पीड़ित लोगों को भी हनुमान मंदिर हर मंगलवार जाना चाहिए। वहीं शनिदेव और राहु की शांति के लिए भी हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी है।इस समय मकर, कुंभ, मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती और वृश्चिक, तुला राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है। शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या लगने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति के लिए हनुमान जयंती के दिन दक्षिणामुखी हनुमान जी के दर्शन करें।उन्हें नारियल अर्पित करें और उनके चरणों में लगा सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। इस तरह हनुमान जी की पूजा से शनिदोषों, शनि महादशा, शनिसाढ़ेसाती और ढैया में राहत मिलती है। पांच बत्तियों वाले दिए में चमेली का तेल डालकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने जलाने से भी और तिल के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करने से लाभ मिलता है।

विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए अविवाहित लड़कियां जरूर करें ये उपाय

सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का विशेष महत्व है। ज्योतिष कुंडली देखकर भूत, वर्तमान और भविष्य की गणना करते हैं। इससे विवाह की भी गणना की जाती है। ज्योतिषियों की मानें तो कुंडली में गुरु और शुक्र विवाह के कारक माने जाते हैं। गुरु लड़कियों की शादी के कारक होते हैं, तो शुक्र लड़कों की शादी के कारक होते हैं। जिन लड़कियों की कुंडली में गुरु मजबूत रहता है। उनकी शादी शीघ्र हो जाती है। वहीं, कमजोर रहने पर शादी में बाधा आती है। इसके अलावा, कई दोषों की वजह से भी शादी में बाधा आती है। इसके लिए कुंडली विश्लेषण जरूरी है। अगर आपकी शादी में भी बाधा आ रही है, तो गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करें। आइए जानते हैं-

- गुरु लड़कियों की शादी के कारक होते हैं। गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति की पूजा-उपासना की जाती है। पीला रंग भगवान श्रीहरि विष्णु को अति प्रिय है। इसके लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें।
- ज्योतिषियों की मानें तो गुरुवार के दिन ब्राह्मण और जरूरतमंदों को पीले रंग के कपड़े और पीले रंग के फल दान करें। इससे गुरु मजबूत होता है। इसके लिए गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करें।
- देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए गुरुवार का व्रत जरूर करें। इस व्रत को करने से गुरु मजबूत होता है। साथ ही भगवान श्रीहरि भी प्रसन्न होते हैं। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं।
- अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, तो गुरुवार के दिन केले के पौधे में हल्दी मिला जल का अर्घ्य दें। इससे गुरु मजबूत होता है। केले के पौधे में जल का अर्घ्य देने तक मौन व्रत धारण करें।
- ज्योतिषियों का कहना है कि गुरुवार के दिन हल्दी मिले पानी से स्नान करना लाभप्रद होता है। इस उपाय को करने से गुरु मजबूत होता है। इससे विवाह में आ रही सभी बाधा दूर हो जाती है।
- गुरुवार के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास करें। व्रत उपवास कम से कम 11 गुरुवार को करें। इस उपाय को करने से जातक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसती है। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं।

बाथरूम का गलत दिशा में होना या उससे जुड़े दोष होना आपकी सेहत के साथ आपकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। जानें घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने व सकारात्मक ऊर्जा आने के लिए बाथरूम से जुड़े ये खास वास्तु टिप्स-

बाथरूम में भूलकर भी न रखें ये चीजें

वरना आर्थिक तंगी का करना पड़ सकता है सामना

वास्तु शास्त्र में बाथरूम-टॉयलेट बनवाने के कई नियम बताए गए हैं। अगर आप भी अपना घर बनवा रहे हैं या बाथरूम रिनोवेट करा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बाथरूम का गलत दिशा में होना या उससे जुड़े दोष होना आपकी सेहत के साथ आपकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। जानें घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने व सकारात्मक ऊर्जा आने के लिए बाथरूम से जुड़े ये खास वास्तु टिप्स-

1. ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाथरूम कभी भी उत्तर-पूर्वी दिशा में नहीं होना चाहिए। यह भी दक्षिण-पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए।
2. बाथरूम या शौचालय में कभी भी बर्तन या तांबे से बनी कोई वस्तु न रखें।
3. नल आग्नेय कोण में नहीं होना चाहिए।
4. बाथरूम में शीशा न रखें।
5. शौचालय और बाथरूम को क्लब नहीं करना चाहिए। नहाने का स्थान और शौचालय स्वच्छ होना चाहिए। स्नान स्थल पवित्र होता है। इसलिए इसमें कमोड न लगाएं।
6. बाथरूम को सीढ़ियों के नीचे न बनाएं।
7. बाथरूम घर का सबसे महत्वपूर्ण एरिया है। इसलिए इसे उत्तर दिशा में रखें। बाथरूम को साफ सुथरा रखें।
8. सारे शैम्पू और साबुन को एक जगह रखें।
9. बाथरूम का फर्श ज्यादा चमकदार नहीं होना चाहिए।
10. बाथरूम की दीवारों को समुद्र के रंग से रंगें।

[भविष्यफल]

मेष

आज आपका मन नए-नए कामों में लगेगा। दोस्तों के साथ मिलकर आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिजूलखर्ची पर कंट्रोल रखें अन्यथा भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। यात्रा योग बन रहे हैं। खरीददारी कर सकते हैं। बच्चों के साथ भावनात्मक सम्बन्ध बनेंगे।

वृष

आज आपकी आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। बिजनेस करने वाले लोगों को मिलाजुला फल मिलेगा। आपके सामने कई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है जिसका सामना करने के लिए आप तैयार रहें। अनजाने लोगों के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत कीजिए।

मिथुन

आज आपका आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। आपको अपनी किस्मत का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे। आपको अपनी मेहनत का मन मुताबिक फायदा मिल सकता है। जो लोग काफी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे.

कर्क

आज आपका आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। आप जिस क्षेत्र में कोशिश करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलने के योग हैं। आपकी किसी बड़ी योजना का अच्छा फायदा मिल सकता है। भविष्य के लिए धन इकट्ठा करने में आप सफल रहेंगे।

सिंह

आज आपका आज का दिन फायदेमंद साबित होगा। रुके हुए कामों में गति आएगी। धार्मिक यात्रा योग। आप अपने विरोधियों को परास्त करेंगे। अचानक अपनों से कोई खुशखबरी मिल सकती है। पैसा कमाने के कई मार्ग हासिल होंगे। आज आप पैसों का उधार लेन-देन मत कीजिए।

कन्या

आज आपका आज का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अचानक किसी महत्वपूर्ण मामले में फैसला लेना पड़ेगा। आपके द्वारा लिया गया फैसला फायदेमंद साबित हो सकता है। प्यार के मामले में आप भाग्यशाली होंगे।

तुला

आज आपका आज का दिन बेहतरीन रहेगा सामाजिक क्षेत्र में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बेरोजगार लोगों को अच्छी नौकरी मिल सकती है। आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। जीवन में आज ढेरों खुशियां आएंगी। जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा। प्रेम जीवन में सुधार आने की संभावना है।

वृश्चिक

आज आपको रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। कार्यालय में आपके कार्यों की सराहना होगी। अचानक लाभ मिलने के योग हैं। आप अपनी मधुर वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। भाग्य प्रबल रहेगा। प्रेम जीवन में रोमांस का अवसर मिल सकता है।

धनु

आज का दिन मौज मस्ती भरा व्यतीत होने वाला है। सामाजिक मेलजोल से आपको खुशी और सुकून मिलेगा। कामकाज में अच्छे नतीजे हासिल होंगे। नौकरी के क्षेत्र का माहौल आपके पक्ष में रहने वाला है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, वह अपने प्रिय के साथ रोमांस भरा पल व्यतीत करेंगे।

मकर

आज आप जरूरतमंद लोगों की मदद करने का मौका मिल सकता है। व्यापार के सिलसिले में लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं। अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसको संतुलित कर देगी। आपको अपना नजरिया सकारात्मक रखना होगा।

कुंभ

आज सकारात्मक बने रहना होगा। आपके मन में कोई पुरानी बात चिंता का कारण बन सकती है। आप कहीं पैसा निवेश कर सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपको अपने किसी जरूरी काम में सफलता हासिल होगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।

मीन

आज का दिन अति उत्तम रहेगा। लाभ के कई अवसर हाथ लग सकते हैं। आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आएगा। खर्चों में कमी आएगी। बच्चों की तरफ से टेंशन कम होगी। पारिवारिक जीवन की परेशानियों का समाधान हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खानपान में रुचि बढ़ेगी।

श्री कृष्ण-राधारानी से संबंधित है ये पवित्र झील

स्नान करने से मिल जाती है हर पाप से मुक्ति

गंगाजल से भी ज्यादा पवित्र मानी जाने वाली यह झील कान्हा नगरी के नाम से मशहूर पुरातन शहर यानी मथुरा में है। इस झील की पौराणिक मान्यता भी है और आज भी लोग यहां का जल ले जाते हैं।

हमारे देश में गंगा को एक नदी नहीं बल्कि गंगा मइया कहते हैं और इसके जल को बेहद पवित्र माना जाता है। पूजा-अनुष्ठान से पहले स्थान को पवित्र करने के लिए गंगाजल का इस्तेमाल किया जाता है और यह मान्यता हर जगह है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी झील भी है जिसके पानी को गंगाजल से ज्यादा पवित्र माना जाता है। अगर नहीं तो चलिए आज आपको यह जानकारी देते हैं।

गंगाजल से भी ज्यादा पवित्र मानी जाने वाली यह झील कान्हा नगरी के नाम से मशहूर पुरातन शहर यानी मथुरा में है। इस झील की पौराणिक मान्यता भी है और आज भी लोग यहां का जल ले जाते हैं। इस बात की जानकारी आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास ने दी। उन्होंने बताया कि इस झील का नाम मानसी गंगा गोवर्धन है और यह मथुरा की सबसे पवित्र झीलों में से एक है। इस झील के जल को गंगाजल से भी ज्यादा पवित्र माना जाता है। इस झील से जुड़ी मान्यता यह है कि भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी इस झील पर नाव में सवारी करते थे।इस झील को लेकर दो पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इसके अनुसार, भगवान कृष्ण ने गोपियों के कहने पर वृष हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहां पर इस झील को प्रकट किया था। इसके बाद इसमें स्नान करके वृष हत्या के पाप से मुक्त हुए थे।

वहीं दूसरी कथा के अनुसार, माना जाता है कि राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण इस झील में नौका विहार करते थे। इसी के कारण यहां पर पूजा करने के साथ दीपदान करने का विधान है।

मानसी गंगा में जो व्यक्ति स्नान करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है।

संक्षिप्त समाचार

सांसद पांडेय ने अनुराग से की मुलाकात खेल अकादमी खोलने की मांग

कबीरधाम। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद संतोष पांडेय ने दिल्ली में केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कबीरधाम में खेलो इंडिया अकादमी खोले जाने का मांग पत्र सौंपा। सांसद संतोष पांडेय ने केंद्रीय खेल मंत्री को लिखे पत्र व उनसे चर्चा के दौरान उन्हें बताया कि खेल के क्षेत्र में कबीरधाम जिले की अलग पहचान है। जिले में खेल प्रतिभा बहुत है। जिले के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में दक्ष हैं और प्रदेश सहित राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। जिले में लगातार खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने, उचित मंच प्रदान करने व उनकी प्रतिभा को और निखारने के लिए कवर्धा में केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खेल अकादमी खोले जाने की आवश्यकता है। इससे खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिलेगा। सांसद पांडेय ने बताया कि खेल हमारे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है। केंद्र सरकार खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है।

तीन दिन में काम पर लौटें संविदा कर्मचारी, नहीं तो एस्मा के तहत कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने हड़ताल पर गए कर्मचारी और अधिकारी को 3 दिन के भीतर काम पर लौटने का आदेश जारी किया है। हड़ताल खत्म कर काम पर नहीं लौटने से उनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। सरकार ने संविदा कर्मचारी और अधिकारियों की मांग पर वेतन वृद्धि की घोषणा की है। इसके बावजूद भी कर्मचारी अधिकारी अपने काम पर अनुपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 की कंडिका 15 (1) के अनुसार आवरण नियम 1965 का उल्लंघन है। एस्मा धारा-4 की उपधारा (1) और (2) के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारी की भर्ती की जाएगी। संविदा कर्मचारी और अधिकारी बुधवार को संवाद रैली करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दंडवत प्रणाम कर जन घोषणा पत्र पर किए गए वादे संविदा नियमितीकरण की मांग को पूरा करने की अपील करेंगे। प्रांतीय मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता सूरज सिंह ने कहा कि संविदा कर्मचारी महासंघ इस कार्रवाई का विरोध करती है। इन 23 दिनों में सरकार चाहती तो संविदा कर्मचारियों से संवाद कर सकती थी, कोई और रास्ता निकल सकता था। शासन बिना संवाद किए कार्रवाई कर रहा है। महासंघ इसका विरोध करता है।

रायपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

रायपुर। मणिपुर में हो रहे हिंसा और अत्याचार को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। मणिपुर में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के संरक्षण में महिलाओं को निर्वस्त्र कर अपमान किया जा रहा है। फिर, भी वहां की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता बृजेश चौरसिया के नेतृत्व में उरला चौक रायपुर में भाजपा की तानाशाही सरकार के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया और पुतला फूंका गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महिला विरोधी, झूठी और जुमलेबाज सरकार है। समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला फूंका है। वहीं, उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की जांच कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे इस प्रकार की हरकत दोबारा किसी और राज्य में न हो। छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी के नेता बृजेश चौरसिया के नेतृत्व में कैफ मंजूर, शानदार हैदर, चंद्र शेखर सिंह, राधेश्याम गौड़, गिरधारी लाल देवांगन और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन मं शामिल रहे।

परिणाम जारी होने से पूर्व चयनित सूची चोरी के आरोप में सहायक अधीक्षक निलंबित

बिलासपुर। कर्मचारी भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले ही चोरी करने के आरोप में दोषी पाते हुए भू अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक खिलेंद्र यादव को निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त समाचारों के अनुसार कलेक्ट्रेट की नजूल शाखा में कर्मचारियों की भर्ती के लिए पूरी प्रक्रिया जूम्मा-जूम्मा ही पूरी हुई थी और मेरिट लिस्ट तैयारी की जा रही थी लेकिन भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पहले ही कार्यालय में पदस्थ सहायक अधीक्षक खिलेंद्र यादव ने कम्प्यूटर में सुरक्षित मेरिट लिस्ट की सूची को कॉपी कर पेन ड्राइव में लेकर अपने पास रख लिया था। बताया जाता है कि इस सूची में चयनित उम्मीदवारों से संपर्क कर वह उनसे पैसों की मांग कर रहा था। जिसकी जानकारी और शिकायत मिलने पर कलेक्टर सौरभ कुमार ने राजस्व सचिव को जांच के लिए उक्त शिकायत भेजी थी। जांच में शिकायत सही पायी गई, सहायक शाखा अधीक्षक खिलेंद्र यादव के पास से पेन ड्राइव को बरामद किया गया, जिसके बाद खिलेंद्र यादव को निलंबित करते हुए रायपुर शाखा में अटैच किया गया है।

नए मतदाताओं से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री युवाओं के मन की पीड़ा और आक्रोश को करें महसूसः अमित

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रथम बार के युवा मतदाताओं से संवाद करने के बजाय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं के मन की पीड़ा और आक्रोश को महसूस करें। अपने पाँच साल के शासनकाल में युवाओं के साथ छल-कपट करके जिस तरह उनकी प्रतिभा और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, उसकी बड़ी कीमत चुकाने के लिए कांग्रेस और भूपेश सरकार को तैयार रहना चाहिए।

साहू ने कहा कि प्रदेशभर में भ्रष्टाचार और घोटालों की कथा लिख चुकी कांग्रेस सरकार ने युवाओं के भविष्य को भी अपने भ्रष्ट आचरण के चलते तबाह करने का काम किया है। लोक सेवा आयोग और व्यावसायिक परीक्षा मंडल में जिस तरह चहेते अफसरों व नेताओं को उपकृत करने के लिए पैसों का खेल खेला गया, उसने युवाओं के सपनों के पंख ही काट डाले, उनके हौसलों, प्रतिभा, परिश्रम व पुरुषार्थ को लहूलुहान करके हताशा के गर्त में धकेल दिया। श्री साहू ने कहा कि बेरोजगारी की दर 0.65 प्रतिशत बताकर झूठे आँकड़े पेश करते हुए रोजगार के नाम पर प्रतिभासंपन्न युवाओं को शराब की कोचियागिरी करते हुए डिलीवरी ब्वॉय बनाकर उनके साथ घिनौना मजाक किया। श्री साहू ने कहा कि 50 लिपिक पदों के लिए 80 हजार और भृत्य के 91 पदों के लिए 2.25 लाख आवेदन जमा होना रोजगार के नाम पर प्रदेश सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रहा है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री साहू ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता का वादा भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता के लिए प्रदेश सरकार ने जटिल मापदंड तय करके इस पूरी योजना को उलझाकर रख दिया। युवाओं की उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश की भूपेश सरकार ने कोई नई पहल नहीं की। केंद्र सरकार द्वारा घोषित मेडिकल कॉलेजों की आधारभूत संरचना खड़ी करने में प्रदेश सरकार की अड़ंगेबाजी से पूरा प्रदेश, खासकर युवा पीढ़ी भली-भांति वाकिफ है।

पुलिस प्रशासन की लाठी केवल बेगुनाहों पर चलती है : शालिनी राजपूत

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन की लाठी केवल बेगुनाहों के ऊपर चलती है। जिस तरह से महासमुंद जिले के कोमाखान तहसील अंतर्गत ग्राम झिटकी की घटना जिसमें एक गरीब परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी बनाने को लेकर नाबालिग छात्रा एवं उनके परिवार ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोमाखान तहसीलदार द्वारा प्रशासन महासमुंद के आदेश निर्देशों का गलत तरीके से पद का दुरुपयोग करने, पानी टंकी निर्माण करने एवं शासन के आदेश का पालन न करते हुए दूहलू पुलिस से सहयोग लेकर अमानवीय ढंग से पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया गया एवं धमकाया गया यहां तक की नाबालिक छात्राओं का हाथ पकड़कर पुलिस द्वारा धक्का-मुक्की भी की गई। शालिनी ने कहा कि घटना से नाबालिग छात्राएं इतनी भयभीत हो गई है कि वे अभी स्कूल भी जाना बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नाबालिग छात्रा एवं उनकी माता के ऊपर पुलिस ने जो मारपीट किया गया एवं बिना जांच के ही परिवार के माता-पिता और दो नाबालिग छात्राओं को पुलिस द्वारा थाने में घंटो तक बिठा के रखा गया वह अमानवीय है।

सिंहदेव की चौपाल में लोटा लेकर पहुंचा बुजुर्ग विकास कार्यों को लेकर सुनाई खरी-खोटी

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने सरगुजा प्रवास के दौरान नगर के कई स्थानों पर जनचौपाल लगाई। हालांकि उपमुख्यमंत्री की यह चुनावी कवायद थी, लेकिन बाबूपारा में देर शाम सिंहदेव की जनचौपाल में लोटा लेकर पहुंचे बुजुर्ग ने प्रशासनिक उदासीनता के साथ नगर में पेयजल एवं सफाई की व्यवस्था को लेकर सिंहदेव को खरी-खरी सुना दी। जनचौपाल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

सरगुजा के प्रवास पर आए उपमुख्यमंत्री सिंहदेव अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 में जनचौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे थे, लेकिन उपमुख्यमंत्री ने यह सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें जन चौपाल में एक बुजुर्ग दीपन चक्रवर्ती की खरी-खोटी सुननी पड़ेगी। जनचौपाल में बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में लोटा लिए पहुंचे। उन्होंने सरकारी तंत्र के ध्वस्त होने का जिक्र करते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। साथ ही नगर निगम के द्वारा वार्डों में किए जा रहे कार्यों की पोल खोल कर रख दी। नगर में खराब सड़कों को लेकर दीपन चक्रवर्ती ने कहा कि जहां मंत्री जाते हैं, वहां की सड़क सुधर जाती है और सफेद लाइन लगा दी जाती है। पूरे शहर की सड़कों का पैचवर्क करें। नगर में पेयजल एवं सफाई को लेकर दीपन चक्रवर्ती ने सिंहदेव को जनचौपाल में आइना दिखाया।

दरअसल, अंबिकापुर नगर निगम में करीब 9 वर्षों से कांग्रेस सत्तासीन है। उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं होने के कारण नगर निगम क्षेत्र में लोगों को पेयजल संकट से भी जूझना पड़ रहा है। नगर निगम के पास पेयजल सप्लाई के लिए बांकी डेम में बमुश्किल छह दिनों का पानी बचा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचाने के लिए डेम में स्लूस गेट तक के हिस्से में जमें गाद को साफ भी किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में पेयजल सप्लाई के लिए केंद्र से मिले 106 करोड़ रुपये में 102 करोड़ खर्च हो गए हैं और लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों की शिकायतों का अंबार जन चौपाल में लगा रहा। मुख्यमंत्री जल्द ही व्यवस्था सुधारने का आश्वासन देते दिखे।

पैरादान घोटाला, गौ माता के नाम पर किया भ्रष्टाचार : अजय चंद्राकर

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कांग्रेस सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। चंद्राकर ने बुधवार को कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह घोटाले की सरकार है। उन्होंने ने कहा कि ऐसी ठग और भ्रष्टाचारी अनैतिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दिसंबर का महीना निर्धारित है।

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछली बार बताया था कि 15 लाख टन पैरा दान में मिला है। इसके परिवहन के लिए सरकार ने 35 करोड़ खर्च किए हैं। अब परिवहन की राशि बढ़कर 53 करोड़ रुपये हो गई है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह नहीं बताया कि उसने पैरा दान कितना किया है। अजय चंद्राकर ने कहा कि वे स्पष्ट रूप से कह सकता हैं कि पैरा दान नहीं किया गया है। उन्होंने 50 ग्रामीणों से पूछा है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर सरकार के पास हिम्मत है तो कहां से कितना पैरा दान मिला, किन ट्रांसपोर्ट से कहां से कहां से आया, इन सभी को सार्वजनिक करना चाहिए।

अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसी भी चीज को सार्वजनिक नहीं करती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने गौ माता के खाने के

नाम पर खुद पैसा खाया है। यह अति निंदनीय है। जो गौ माता के नाम पर, गोबर के नाम पर और भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार करती है। ऐसी सरकार को भगाना जरूरी है और उसे हटाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ को इनके भ्रष्टाचार से बचाना जरूरी है। गौ माता के खाने के नाम पर घपलेबाज सरकार ने पैसा खाने का काम किया है। फर्जी परिवहन दिखाकर 53 करोड़ का घोटाला इस सरकार ने किया है। दिसंबर महीने में इस तरह की ठग सरकार को जनता उखड़ फेंकेगी। सभी भ्रष्टाचारियों को भाजपा जेल भेजेगी।

राम-वन-गमन पथ की पवित्र माटी से चंदखुरी की पावन धरती पर होगा पौधरोपण

- सुकमा के रामाराम और कोरिया के सीतामढ़ी-हरचौका के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने निजी एफएम रेडियो चैनल की पहल राम पथ से राम वन का शुभारंभ किया और इसमें शामिल दो वाहनों को सुकमा जिले के रामाराम और कोरिया जिले के सीतामढ़ी-हरचौका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राम पथ से राम वन के माध्यम से भगवान राम की छत्तीसगढ़ यात्रा में शामिल प्रमुख स्थानों की मिट्टी एकत्रित कर इसके अंतिम पड़ाव माता कौशल्या धाम चंदखुरी में वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही इस यात्रा के दौरान एफएम चैनल द्वारा भगवान श्रीराम की छत्तीसगढ़ यात्रा से जुड़ी कहानियों और मान्यताओं को भी आमजनों के साथ साझा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर रामपथ से रामवन मुहिम से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और इस पहल की सराहाना भी की। उन्होंने कहा कि भगवान राम हम सबके है और छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल है। मुख्यमंत्री ने कहा हम भाग्यशाली है कि हमें राम-वन-गमन पथ को विकसित करने का अवसर मिला और 09 प्रमुख स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है। शासन की इस पहल से हजारों लोग और संस्थाएं स्वस्फूर्त जुड़ते जा रहे है, यह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की माटी में भगवान राम बसते है और इस पवित्र मिट्टी को लाकर वृक्षारोपण का पुनीत कार्य किया जाएगा। यह वृक्ष भगवान राम के यात्रा की स्मृति का प्रतीक होगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में वनवास काल में भगवान राम की छत्तीसगढ़ यात्रा में शामिल स्थानों को राम-वन-गमन पथ के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। शासन की इस पहल से लगातार अन्य लोग भी जुड़कर अपनी भगीदारी निभा रहे है। एफएम चैनल द्वारा रामपथ से रामवन की पहल से राम-वन-गमन पथ के प्रमुख स्थानों जैसे कोरिया के सीतामढ़ी-हर चौका, सरगुजा के रामगढ़ जांजगीर चांपा के शिवरीनारायण, बलौदा बाजार के तुरतुरिया, रायपुर के चंदखुरी, गरियाबंद के राजिम, धमतरी के सिहावा, बस्तर के जगदलपुर और सुकमा के रामाराम से मिट्टी एकत्रित कर माता कौशल्या धाम परिसर चंदखुरी में वृक्षारोपण किया जाएगा।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजे श्री डॉ. महंत रामसुंदर दास, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री अटल श्रीवास्तव सहित अन्य प्रतिनिधि गण उपस्थित थे।

मणिपुर की घटना को छत्तीसगढ़ से जोड़ना ठीक नहीं : नंदकुमार साय

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष नंदकुमार साय ने कहा कि, छत्तीसगढ़ (सुकमा) हो या मणिपुर, कहीं भी महिलाओं और बच्चियों के साथ अनाचार, दुष्कर्म हो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका विरोध होना चाहिए। इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि, मणिपुर की घटना को छत्तीसगढ़ से जोड़ना ठीक नहीं है। जनजाति वर्ग कूकी और मैतेई के बीच हिंसा हो रही है। कहा कि, सरकार की देरी के चलते स्थिति बेकाबू हुई है। कैबिनेट मंत्री साय बुधवार को मीडिया से बात कर रहे थे।

अपने एक दिवसीय दौरे पर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़) जिला पहुंचे नंद कुमार साय ने कहा कि, उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना अभिमत भेजा है कि सबसे पहले मणिपुर में फोर्स लगा कर हिंसा रोकी जानी चाहिए। उनकी मांगों पर बैठकर विचार किया जाना चाहिए। रणभूमि पर इसका इलाज नहीं हो सकता। इसके बाद वहां बैठकर चर्चा करके उनकी मांगों पर विचार किया जाए और संविधान के अनुसार निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले वहां शांति बहाली करें।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने और सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर साय ने कहा कि, इससे चुनाव में फायदा होगा। ढाई-ढाई साल का जो विवाद था, वह भी इसकी एक वजह थी। पीएम के लगातार हो रहे दौरे को लेकर कहा कि, प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ से बहुत प्रेम हो गया है। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इससे पहले प्रेस क्लब पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद कुमार साय ने पंडित माधव राव सप्रे की प्रतिमा पर माल्यर्पण किया। पत्रकारों से चर्चा के बाद साय अमरकंटक रवाना हो गए। वहां नर्मदा दर्शन के बाद रतनपुर मां महामाया के दर्शन करेंगे और फिर रायपुर रवाना होंगे।

2 अगस्त को मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ शुरू हो जाएगी निर्वाचन की तैयारी

- 31 अगस्त तक नाम जोडऩे, काटने एवं संशोधन के लिए दावा-आपत्ति लिए जाएंगे, 4 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
- 12-13 अगस्त एवं 19-20 अगस्त को मतदान केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे विशेष शिविर

रायपुर। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के पूर्व प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अगस्त को राज्य में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा फॉर्म-5 में मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन करने के साथ-साथ 1 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि के सम्बन्ध में दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाने नोटिस जारी किया जाएगा। इसी दिन राज्य में विशेष ग्राम सभा में मतदाता सूची का वाचन भी किया जाएगा। विधानसभा एवं जिला स्तर पर भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन में मतदाता सूची को शुद्ध बनाने जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यह मतदाता सूची राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट में भी होस्ट की जाएगी। इसकी एक फोटोयुक्त हार्ड एवं एक फोटोरहित सॉफ्ट कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी जिला स्तर पर बैठक कर प्रदान की जाएगी। मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के दिन से 31 अगस्त तक निर्धारित प्रारूपों में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। 30 दिनों की इस अवधि के दौरान चार दिन, 12-13 अगस्त (शनिवार-रविवार) और 19-20 अगस्त (शनिवार-रविवार) को बूथ स्तर पर विशेष शिविर का भी आयोजन होगा। इस दौरान 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। मृत, डुप्लीकेट या स्थाई रूप से

स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। पूर्व से पंजीकृत मतदाता के विवरण में किसी प्रकार के संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप और वोटर सर्विस पोर्टल भी उपलब्ध हैं। बीएलओ द्वारा फॉर्म भरने के लिए बीएलओ एप का प्रयोग किया जाएगा।

31 अगस्त तक प्राप्त होने वाले दावा-आपत्तियों की साप्ताहिक सूची सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक कर दी जाएगी। साप्ताहिक रूप से इस सूची का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशन किया जाएगा। 22 सितम्बर तक सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण कर 4 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन फॉर्म-16 में किया जाएगा। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची पुनः वेबसाइट में होस्ट करने के साथ-साथ इसकी एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर प्रदान की जाएगी।

छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए पुनरीक्षण के दौरान सघन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस दौरान छूटे हुए युवाओं एवं समाज के वंचित वर्गों को अधिक से अधिक जागरूक कर उनका नाम मतदाता सूची में जोडऩे के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में चार लाख 25 हजार 698 मतदाता 18-19 आयु वर्ग के हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या एक लाख 47 हजार 364 तथा 767 तृतीय लिंग समुदाय के मतदाता हैं। राज्य में मतदाता सूची का लिंगानुपात 1002 है तथा मतदाता-जनसंख्या अनुपात 64.65 प्रतिशत है। श्रीमती कंगाले ने प्रदेश के नागरिकों से पुनरीक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।

प्रदेश के 10 लाख आदिवासियों की जिंदगी बदल जायेगी : साव

■ भाजपा का निर्णय आदिवासी समाज को 1, 2 दिन नही बल्कि पीढ़ियों तक लाभ देगाःडॉ रमन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने 12 जनजाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार व लाभ प्रदान करने के लिए कानून बनाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के बाद से महज़ लिपिकीय त्रुटि के कारण पिछले 70 वर्ष से अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण के लाभ से वंचित 12 जनजाति समुदायों के लोग अब अपना स्वर्णिम भविष्य गढ़ पाएंगे। श्री साव ने कहा कि भारत के, विशेषकर आदिवासी प्रदेश छत्तीसगढ़ के इतिहास में कल 25 जुलाई का दिन मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने देश के 12 प्रमुख समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर लिया। कल राज्यसभा से भी यह विधेयक पारित होने के बाद अब क़ानून बन गया है। इससे इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रदेश भाजपा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा व केन्द्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का बार-बार अभिनंदन करती है।

इन जातियों को मिलेगा लाभ

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने सूची में शामिल जातियों का विवरण दिया। भारिया भूमिया के समानार्थी भूईया, भूईयाँ, भूयां, धनवार के समानार्थी धनुहार धनुवार, नगेसिया, नागासिया के समानार्थी किसान, सावर, सवरा के समानार्थी सौंरा, संवरा, धांगड़ के साथ प्रतिस्थापित करते हुए सुधार, बिंझिया, कोडाकू के साथ साथ कोड़ाकू, कोंध के साथ-साथ कोंद, भरिया, भारिया, पंडो, पण्डो, पन्डो को जनजाति वर्ग में शामिल किया गया है।

संसद में चर्चा

श्री साव ने कहा कि कल इस संबंध में संसद में प्रस्तुत विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेकर विभागीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने सही कहा कि आज का यह दिन न केवल छत्तीसगढ़ में निवासरत आदिवासी समुदायों के लिए, अपितु देशभर में निवासरत 700 (सात सौ) जनजाति समुदायों के लिए ऐतिहासिक है। जिन 12 जातियों को सूची में लाने के लिए यह संशोधन प्रस्ताव लाया गया है, उनमें से 10 जातियाँ लिपिकीय त्रुटियों के कारण संविधान प्रदत्त अधिकारों और लाभ से आजादी के इतने वर्षों बाद भी वंचित थीं। यहां विशेष तौर विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कही जाने वाली विशेष पिछड़ी पण्डो जनजाति भी आजादी के 75 वर्ष बाद भी अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं किए गए थे।

कांग्रेस सांसदों का इस महत्वपूर्ण विधेयक की चर्चा में भाग न लेना दुर्भाग्यजनक

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है जहाँ आदिवासियों को त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन सूची से बाहर जनजाति समुदायों के लोग किसी भी तरह चुनाव में भाग नहीं ले पाते थे। अब जा कर सभी अनुसूचित जनजाति समुदायों को उनका अधिकार मिला है। श्री साव ने कहा कि इस विषय का सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि सदन में जब इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही थी तब वहां छत्तीसगढ़ कोटा से आने वाले सभी कांग्रेसी सदस्य अनुपस्थित थे। भले वोट की राजनीति के मजबूरीवश कांग्रेस सड़क पर कुछ भी कहती रहे, लेकिन जब भी ऐसे कोई विषय परिणाम तक पहुँचने वाले होते हैं, तब कांग्रेस अड़ंगा लगाती ही है। आखिर 50 से अधिक वर्षों तक इसी कांग्रेस ने इन तमाम मामलों को लटकाए भी रखा था।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि ऐसे मामले में जान-बूझ कर कांग्रेस के अनुपस्थित होने या वंचित वर्ग के कल्याण से संबंधित का यह कोई पहला मामला भी नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का भी विरोध कर राज्यसभा में कांग्रेस ने उसे तब पारित नहीं होने दिया था। इसी तरह आदिवासी और पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के विरुद्ध प्रदेश की कांग्रेस सरकार कोर्ट में अपने लोगों से मुक़दमा करा कर, अपने महाधिवक्ता को कोर्ट में सुनवाई के दिन अनुपस्थित करा कर जान बूझ कर हार जाना और फिर मुक़दमा करने वालों को पद देकर पुरस्कृत करना आदि निंदनीय हथकंडे हमेशा कांग्रेस अपनाती रही है। कांग्रेस को वंचित तबकों के साथ ऐसे खिलवाड़ से बाज आना चाहिए। श्री साव ने कहा कि इन तमाम हथकंडों से पार पाते हुए आदिवासी समाज ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन जाति समुदायों के छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने के बाद इन्हें शासन की अनुसूचित जनजातियों के लिये संचालित योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। छात्रवृत्ति, रियायती ऋण, अनुसूचित जनजातियों के बालक-बालिकाओं के छात्रावास की सुविधा के साथ शासकीय सेवा और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। प्रेस वार्ता में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम,प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता,प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी,सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल मौजूद रहे।

कई वर्षों की पीड़ा से आदिवासी समाज को मुक्ति मिली : डॉ. रमन

पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि आजादी के बाद से जिस पीड़ा को 12 अनुसूचित जनजातियां झेल रही थी उससे उन्हें अब मुक्ति मिली है। महज मात्रात्मक त्रुटि की वजह से इन 12 जनजातियों की पीढ़ियों को अपने अधिकारों और संविधान प्रदत्त लाभ से वंचित रहना पड़ा। इन समुदायों के लाखों लोग अब शिक्षा, स्वास्थ्य और संविधानिक अधिकार व आरक्षण का लाभ मिलेगा। डॉ. सिंह ने कहा कि यह काम एक दो दिनों के लिए नहीं हुआ है बल्कि इन जनजातियों की पीढ़ियों को इसका स्थायी रूप से लाभ मिलेगा। डॉ. सिंह ने इसके लिए प्रदेश और प्रदेश की इन जनजातियों समुदायों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा व केन्द्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का आभार माना।

डॉ. सिंह ने इन जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ हुई चर्चा तथा पत्र व्यवहार का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार से संविधान में आवश्यक संशोधन कर अनुसूचित जनजाति समुदायों सूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने तत्काल पहल की और आदेश किया। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए इस विधेयक को पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में पारित करवाया और उसे कानून का जामा पहनाया। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र व विशेष पिछड़ी जाति पंडो जनजाति को अनुसूचित जनजाति का पीढ़ियों से अधिकार व लाभ नहीं मिलना सबसे बड़ी विसंगति थी। यह विसंगति अब दूर हो गई है। डॉ. सिंह ने कहा कि भाजपा शीघ्र ही इन समुदायों के साथ मिलकर उनकी खुशी में शामिल होगी।

सुकमा में 5 वर्षीय आदिवासी बच्ची से रेप का मामला

एर्राबोर पहुंचा भाजपा जांच दल

■ जांच दल ने कहा छात्रावास के हाल बेहाल, न कैमरा, न आदिवासी महिला अधीक्षिका, न अब तक कोई गिरफ्तारी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुकमा जिले के एर्राबोर थाना अंतर्गत एक आवासीय कन्या विद्यालय में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच करने पहुंची भाजपा की पांच सदस्यीय जांच समिति को छात्रावास में शासन प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन ग्रामीणों व आदिवासियों के आक्रोश के चलते जांच समिति को छात्रावास में जाने की अनुमति दी गई। बाद में समिति की संयोजक व विधायक रंजना साहू ने मीडिया से चर्चा के दौरान सभी अपराधियों, छात्रावास अधीक्षिका व सह अधीक्षिका पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। श्रीमती साहू ने इस घटना के लिए मंत्री कवासी लखमा को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस मामले को दबाने में उनकी भी भूमिका है। अब छत्तीसगढ़ में यह अंधेरगर्दी नहीं चलेगी।उल्लेखनीय है कि सुकमा जिले के एर्राबोर थाना अंतर्गत ग्राम पोटा केबिन के शासकीय कन्या आवासीय विद्यालय में पहली कक्षा की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना को गंभीरता से लिया है। भाजपा प्रदेश इकाई द्वारा इस घटना के तथ्यों व घटनाक्रम का विश्लेषण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए गठित जांच समिति बुधवार को एर्राबोर के ग्राम पोटाकेबिन स्थित आवासीय विद्यालय पहुंची। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक रंजना साहू ने संयोजकत्व में गठित इस जांच समिति में भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व मंत्री लता उसेंडी, प्रदेश मंत्री ओजस्वी मंडावी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत एवं प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य सुधीर पांडे सम्मिलित हैं।

विधानसभा चुनाव को लेकर डीजीपी ने ली बैठक

रायपुर। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीमा से लगे दूसरे राज्यों की पुलिस से भी तालमेल बिठाने की कवायद की जा रही है। इसी के चलते हैदराबाद में छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में समन्वय बैठक आयोजित की गई।

यह बैठक छत्तीसगढ़ के ष्ठतक अशोक जुनेजा और महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की उपस्तिथि में आयोजित की गई। इस समन्वय बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नक्सल विरोधी अभियान, कानून व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।चारों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों द्वारा राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में अपेक्षित पुलिस बंदोबस्त, कानून व्यवस्था और नक्सल गतिविधियों से संबंधित विषयों पर प्रस्तुतीकरण दी गई। इस बैठक में प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में आने वाले थाना प्रभारी और पुलिस से जुड़े अन्य अधिकारियों को बुलाया गया।

योग शिविर में प्राणायाम, आसन और योग दर्शन सीख रहे प्रतिभागी

रायपुर। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा दुर्ग संभाग के लिए सात दिवसीय संभाग स्तरीय नि:शुल्क आवासीय योग प्रशिक्षण शिविर राजधानी रायपुर के फुण्डहर स्थित योग भवन में संचालित किया जा रहा है। इससे पूर्व रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए योग प्रशिक्षण शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन योग आयोग द्वारा किया गया है। शिविर में प्रतिभागियों को योग की विभिन्न प्रणालियों की जानकारी सहित मानव शरीर में योग के फायदों के बारे में बताया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा, सचिव श्री एम.एल. पाण्डेय सहित योग प्रशिक्षक गण उपस्थित थे।

योग सत्र के दौरान विशेषज्ञों के द्वारा अष्टांग योग, यम के नियम, आसन का परिचय एवं महत्व की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य एवं रोगों के प्रति योग का समग्र दृष्टिकोण, मानव शरीर का संक्षिप्त परिचय एवं आसन की समान्य समस्या एवं समाधान, यौगिक सकारात्मक दृष्टिकोण चित्त प्रसाद, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम एवं सूर्यनमस्कार और उसके प्रकार, योग दर्शन, प्रणिक ऊर्जा के विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही प्रतिभागियों को प्रतिदिन सुबह श्री छबि राम साहू और श्रीमती ज्योति साहू द्वारा योगाभ्यास भी कराया जा रहा है।

छत्तीसगढ़/राजधानी — प्रमुख समाचार

कांग्रेस के प्रयासों से 12 जाति समूह आदिवासी वर्ग में शामिल

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार के प्रयासो और विधिसम्मत की गयी अनुशंसा से ही 12 जाति समूहों के लोगो को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को इस आशय का पत्र भी 11 फरवरी 2021 को लिखा था। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुये भी इन जाति समूहों को अनु.जनजाति में शामिल करने के लिये आंदोलन किया था। स्वंय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुये सौरा समाज सहित अन्य समाजो के आंदोलनों में लगातार शामिल कर इनकी मांगो के लिये आवाज उठाते रहे है। 15 साल तक आदिवासियों का शोषण करने वाले रमन सिंह और भाजपाई 12 जाति समूहों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने किये जाने पर श्रेय लेने की होड में परेशान हो रहे है। रमन सिंह और भाजपा के नेतागण श्रेय लेने के लिये बयान दे रहे कि यह उनके प्रयासो से हुआ है। 15 साल की सरकार के दौरान उन्होंने इस दिशा में क्या सार्थक पहल किया था? उनकी सरकार के आखिरी चार साल में केन्द्र और राज्य दोनो जगह भाजपा की सरकार थी रमन सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में प्रभावशाली भी थे। इन चार सालों में इन 12 उपजातियों की मांगो के अनुसार केन्द्र से निर्णय क्यों नहीं करवाया? भाजपा और रमन सिंह नहीं चाहते थे।

कांग्रेस ने जितना छल किया सीएम युवाओं को बताएः अमित

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू ने बुधवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि प्रथम बार के युवा मतदाताओं से संवाद करने के बजाय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं के मन की पीड़ा और आक्रोश को महसूस करें। श्री साहू ने कहा कि अपने पाँच साल के शासनकाल में कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने युवाओं के साथ छल-कपट करके जिस तरह उनकी प्रतिभा और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, उसकी बड़ी कीमत चुकाने के लिए कांग्रेस और भूपेश सरकार को तैयार रहना चाहिए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री साहू ने कहा कि प्रदेशभर में भ्रष्टाचार और घोटालों की कलंक कथा लिख चुकी प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने युवाओं के भविष्य को भी अपने भ्रष्ट आचरण के चलते तबाह करने का काम किया है। लोक सेवा आयोग और व्यावसायिक परीक्षा मंडल में जिस तरह चहेते अफसरों व नेताओं को उपकृत करने के लिए पैसों का खेल खेला गया, उसने युवाओं के सपनों के पंख ही काट डाले, उनके हौसलों, प्रतिभा, परिश्रम व पुरुषार्थ को लहूलुहान करके हताशा के गर्त में धकेल दिया। बेरोजगारी की दर 0.65 प्रतिशत बताकर झूठे आँकड़े पेश करके अपने मुँह मियाँ मिठ्ठू बनने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने रोजगार के नाम पर प्रतिभासंपन्न युवाओं को शराब की कोचियागिरी करते हुए डिलीवरी ब्वॉय बनाकर उनके साथ घिनौना मजाक किया। श्री साहू ने कहा कि 50 लिपिक पदों के लिए 80 हजार और भृत्य के 91 पदों के लिए 2.25 लाख आवेदन जमा होना रोजगार के नाम पर प्रदेश सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रहा है।

भाजपा सिर्फ राजनीति करने जांच दल बनाया : ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सुकमा जिले के पोटा केबिन में हुई मासूम बच्ची के साथ दुराचार की घटना बेहद निंदनीय है इस मामले में एफ आईआर दर्ज की गई है आश्रम की अधीक्षिका और सह अधीक्षका को निलंबित कर दिया गया है। दुराचार

के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। इस पूरे मामले में भाजपा का असंवेदनशील चेहरा सामने आया है पोटा केबिन के मामले में भाजपा सिर्फ राजनीति करने जांच दल बनाया है जिसका मूल मकसद मणिपुर की घटनाओं का बचाव करना है।मणिपुर की भाजपा सरकार की कायरता, निर्लज्जता, बेशर्मी असफलता पर पर्दा करना है। भाजपा का मकसद मणिपुर में हुए हिंसा दंगा आगजनी की घटना महिलाओं का दुर्व्यवहार से देश की जनता का ध्यान हटाना है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराधी पकड़े जाते हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती है वहीं भाजपा शासित राज्यों में आदिवासी दलित कमजोर वर्ग असुरक्षित है मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके जिस प्रकार से घुमाया गया उनके साथ दुराचार हुआ भाजपा की नेत्रियां इस मामले में मौन क्यों हैं?मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में भी दलित महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था।

पुलिस प्रशासन की लाठी केवल बेगुनाहों पर चलती है : शालिनी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन की लाठी केवल बेगुनाहों के ऊपर चलती है। जिस तरह से महासमुंद जिले के कोमाखान तहसील अंतर्गत ग्राम झिटकी की घटना जिसमें एक गरीब परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित

किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी बनाने को लेकर नाबालिग छात्रा एवं उनके परिवार ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोमाखान तहसीलदार द्वारा प्रशासन महासमुंद के आदेश निर्देशों का गलत तरीके से पद का दुरुपयोग करने, पानी टंकी निर्माण करने एवं शासन के आदेश का पालन न करते हुए टूहलू पुलिस से सहयोग लेकर अमानवीय ढंग से पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया गया एवं धमकाया गया यहां तक की नाबालिग छात्रों का हाथ पकड़कर पुलिस द्वारा धक्का-मुक्की भी की गई।भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि घटना से नाबालिग छात्राएं इतनी भयभीत हो गई है कि वे अभी स्कूल भी जाना बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नाबालिग छात्रा एवं उनकी माता के ऊपर पुलिस ने जो मारपीट किया गया एवं बिना जांच के ही परिवार के माता-पिता और दो नाबालिग छात्राओं को पुलिस द्वारा थाने में घंटो तक बिठा के रखा गया वह अमानवीय है। पीड़ित परिवार ने पानी टंकी को लेकर कलेक्टर से जन चौपाल में शिकायत की थी जिसमें प्रशासन ने पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया था।

नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आएः दीपक

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीपक म्हस्के ने प्रदेश सरकार पर संविदा, अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित ना करने पर कहा कि नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस अब नोटिस देने लगी है। श्री म्हस्के ने एस्मा लागू कर हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई करने को अन्यायपूर्ण बताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री म्हस्के ने कहा कि सरकार ने इन कर्मचारियों में फूट डालने के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की है, जबकि सरकार अच्छी तरह जानती है कि हजारों हड़ताली कर्मचारियों में से महज दो-तीन हजार पे बैंड कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा। श्री म्हस्के ने कहा कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणापत्र में संविदा, अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। पाँच वर्ष का पूरा कार्यकाल बीतने को है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। प्रदेश सरकार ने तो कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ अपने पूरे कार्यकाल में केवल और केवल छलावा ही किया है। केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता और टीए-डीए देने की घोषणा करने में भी इस सरकार को पौने पांच साल लग गए! आज सरकार को अपना वादा याद दिलाने और अपने साथ इंसाफ के लिए हजारों कर्मचारी जब हड़ताल करने को विवश हैं, तब आपातकाल के विचार से पोषित कांग्रेस को यह भी गवारा नहीं है कि कर्मचारी उसके खिलाफ आवाज उठाएँ।

विद्युत कंपनी व फेडरेशन की बैठक संपन्न,अनेक मांगों पर निर्णय

रायपुर। 26 जुलाई को विद्युत कंपनी के सभा कक्ष में श्री अंकित आनंद,अध्यक्षङ्कविद्युत कंपनीज की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन 01 की मांगों पर प्रबंधन एवं यूनियन प्रतिनिधियों की विस्तार से चर्चा संपन्न हुई,बैठक में संगठन के 11 बिंदु के मांग पत्र के अधिकांश मांगों पर संगठन के तार्किक अभिमत से सहमत होकर प्रबंधन द्वारा तत्काल निर्णय लिया गया जिसमें 2018 बैच के 700 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान अप्राप्त इस संवर्ग के अन्य कर्मचारियों के अनुरूप प्रभाव सील महंगाई भत्ता एरियर्स के साथ दिए जाने का निर्णय लिया गया, साथ ही 2004 से 2023 के मध्य एन पी एस योजना के अंतर्गत दिवंगत कर्मचारी के परिवार को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत परिवार पेंशन का लाभ दिया जायेगा जिससे लगभग 1000 परिवार

लाभान्वित होंगे,कार्यालय सहायक 3 के लिए 5000 केजी 4 डिप्रेशन मार्च 2023 से प्रभावशील होगा,कंपनी में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों की विभागीय एवं सीधी भर्ती प्रक्रिया 10 दिनों में प्रारंभ होगी,संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर संगठन के सुझाव से सैद्धांतिक रूप से सहमत होते हुए शासन से चर्चा एवम विधिक अभिमत पश्चात विचार किया जाएगा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा स्वीकृत,28 जुलाई को सभी संगठनों के समक्ष योजना का प्रस्तुतिकरण होगा।

कंपनी अध्यक्ष ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर स्पष्ट किया कि इसका निर्णय शासन की ओर से लिया जाना है,संचालक मंडल द्वारा मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री को कर्मचारियों की मांग से अवगत कराते हुए जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा,2004 के पूर्व विज्ञापित पदों पर नियुक्त एनपीएस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लाभ संबंधी आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं जिसमें 2003 के शेष 495 कर्मचारी जिन्हें संविदा नियुक्ति देकर नियमित किया गया है तत्संबंध में संचालक मंडल के प्रस्ताव से विधिक मत लेकर पुरानी पेंशन सुविधा दी जाएगी,इसके अलावा इंजीनियरों को 3न तकनीकी भत्ता का निर्णय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है

भूपेश सरकार ने 36 में 34 वायदे पूरा किया : कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 15 सालों तक झूठ फरेब की सरकार चलाने वाले वायदा खिलाफी करने वाले डॉ. रमन सिंह एक बार फिर से झूठ बोल रहे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के वायदों को पूरा नहीं किया सिर्फ 19 वायदे पूरे किये है। जबकि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में कुल 36 वायदे किये थे जिसमें से हमने 34 वायदे पूरा कर दिया है। हम रमन सिंह को अपने घोषणा पत्र की प्रति जिसमें हमारे वायदों का पूरा हिसाब है और भाजपा के संकल्प पत्र जो उन्होंने 2003 और 2008 तथा 2013 में जनता से वायदा किया था दोनों को भेज रहे है जिसको वे पढ़ ले तो शायद उन्हें अपने आप को आईने में देखने में शर्म आयेगी जिस प्रदेश

ने उनको 15 सालों तक सिर आंखों पर बैठाया उसके साथ उन्होंने धोखा किया था। हमने जनघोषणा पत्र के 34 वायदे पूरा किया।

शराबबंदी, लोकपाल के दो वायदे अधूरे है जिसमें हमने शराब बंदी के लिये ठोस प्रयास शुरू किया है। 100 से अधिक दुकानों को बंद किय। आज हमारे प्रयासों से रमन सरकार के समय जो छत्तीसगढ़ शराब की खपत में प्रति व्यक्ति गोवा के बाद पहले नंबर पर था वह अब 18वें नंबर पर है। जनघोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने का काम हमारी सरकार बनने के पहले घंटे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू किया था, किसानों की कर्जा माफ करने से वह अनवरत पांच सालों तक चलते रहा, यही कारण है कि कांग्रेस की सरकार के प्रति जनता का भरोसा रोज बढ़ते जा रहा है, 5 उपचुनाव, नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव सभी में जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रति भरपूर आर्शिवाद दिया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.